राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

RIN. No. UHIN/2012/43078

स्वतंत्र प्रभात

जो लिखेगा, वही टिकेगा

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें........
9511151254

@swatantraprabhatmedia | @swatantramedia | RNI.No. UPHIN/2019/79073 (epaper.swatantraprabhat.com) | @SwatantraPrabhatonline | news@swatantraprabhat.com

लखनऊ से प्रकाशित एंव अयोध्या, प्रयागराज, मिर्जापर, गोरखपुर, बरेली, बुंदेलखंड, उत्तराखंड, देहरादून

सीतापुर, बुधवार, 04 जून 2025

वर्ष 13, अंक 56, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखण्ड, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

सरकार उपेक्षा से, भड़का राशन वितरकों का गुस्सा......03

बाढ़ में 15 से अधिक गांव क्षतिग्रस्त मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाके आमतला का किया दौरा...04

अडानी ग्रुप पर ईरान से पेट्रोकेमिकल आयात का शक, अमेरिका ने शुरू की जांच- रिपोर्ट

स्वतंत्र प्रभात

नई दिल्ली- अमेरिका के न्याय विभाग (यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस) ने अडानी समूह की उस भूमिका की जांच शुरू की है जिसमें उस पर ईरान से पेट्रोकेमिकल उत्पाद (विशेष रूप से एलपीजी) आयात करने का संदेह है. यह जानकारी वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दी गई है. यह जांच उस वक्त हो रही है जब अडानी समूह भ्रष्टाचार के एक अलग मामले में समझौते की कोशिश कर रहा है. इन आरोपों को 'बेबुनियाद' बताते हुए अडानी समूह ने किसी भी तरह की अमेरिकी प्रतिबंधों को चकमा देने या ईरानी मूल के एलपीजी से जुड़े व्यापार से इनकार किया है. अडानी के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि उन्हें इस तरह की किसी अमेरिकी जांच की जानकारी नहीं है। प्रवक्ता ने कहा, 'वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट का समय यह दर्शाता है कि इसका उद्देश्य न्याय विभाग में चल रहे अभियोग को प्रभावित करना है।'

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इससे पहले 13 अप्रैल को रिपोर्ट किया था कि गौतम अडानी के वकीलों ने अमेरिका के न्याय विभाग से उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे को खत्म करने की अपील की थी. इन मुकदमों में अडानी पर भारत में सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत देने का आरोप है।

यह आरोप अक्टूबर 2024 में सार्वजनिक हुए थे, जिसमें अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और तीन कंपनियों के छह अन्य अधिकारियों का नाम शामिल था। एक समानांतर मुकदमे में अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने गौतम और सागर अडानी पर संघीय प्रतिभूति कानूनों के धोखाधड़ी विरोधी प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया है।

5 मई को ब्लूमबर्ग ने बताया था कि अडानी के वकीलों और ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के बीच बातचीत तेज हो गई है और आने वाले एक महीने में किसी समझौते तक पहुंचा जा सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की 2 जून की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि अमेरिकी अभियोजक (प्रॉसिक्यूटर) अडानी एंटरप्राइज़ेज के लिए एलपीजी की ढुलाई में इस्तेमाल किए गए कुछ टैंकरों की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे हैं।

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खाड़ी के बंदरगाहों और अडानी द्वारा संचालित मुंद्रा बंदरगाह के बीच यात्रा करने वाले एलपीजी टैंकरों के एक समूह का भी पता लगाया. रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें इन जहाजों की गतिविधियां छिपाने की कोशिश के कुछ साफ-साफ संकेत मिले, जिनमें जहाज की लोकेशन बताने वाली स्वचालित पहचान प्रणाली (एआईएस) में हेरफेर करना शामिल है.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईरानी तेल और गैस उत्पादों के खरीदार अक्सर ओमान और इराक से बने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हैं। इस जांच का फोकस SMS Bros नामक एक पनामा-पंजीकृत टैंकर जहाज़ पर है, जिसे बाद में Neel नाम दिया गया. एआईएस डेटा के अनुसार, यह जहाज 3 अप्रैल को इराक के खोर अल जुबैर बंदरगाह पर था. लेकिन उसी दिन की सैटेलाइट तस्वीरों में वहां इस जहाज का कोई निशान नहीं मिला. इसके बजाय, उसी तरह की बनावट वाला एक जहाज ईरान के टोंबाक में एलपीजी टर्मिनल पर खड़ा दिखा. चार दिन बाद यह टैंकर यूएई के तट के पास नजर आया और उसके डेटा से पता चला कि वह पानी में कुछ नीचे बैठा हुआ था – जिससे संकेत मिलता है कि उसने माल लादा था।

जहाज ने ओमान के सोहर बंदरगाह के पास लंगर डालने का सिग्नल भेजा था, लेकिन वह वहां वास्तव में लंगर डालता हुआ कभी दिखा ही नहीं. दो दिन बाद अडानी ग्लोबल

पीटीई ने इस जहाज को लगभग 11,250 मीट्रिक टन एलपीजी लोड करने और उसे भारत के मुंद्रा बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए अनुबंधित किया. भारत के कस्टम रिकॉर्ड्स के मुताबिक, 17 अप्रैल को अडानी इंटरप्राइजेज ने एक ऐसा ही माल आयात किया, जिसकी कीमत 70 लाख डॉलर से थोड़ी अधिक थी।

SMS Bros (अब Neel) के दस्तावेजों में पहले भी कई विसंगतियां पाई गई हैं. जून 2024 के एक बांग्लादेशी पोर्ट के दस्तावेज में इसका उल्लेख ईरानी मूल के एलपीजी की डिलीवरी के लिए किया गया था, जबकि एआईएस डेटा में इसे इराक की ओर जाते हुए दिखाया गया था—यह पैटर्न अप्रैल वाले मामले से मेल खाता है।

अडानी के मुंद्रा बंदरगाह से जुड़े तीन और एलपीजी टैंकरों की गतिविधियों में भी गड़बड़ियां मिली हैं. एक जहाज, जिसे उसी कंपनी ने संचालित किया जो हृद्गद्ग्ध को मैनेज करती है, वह अमेरिकी सीनेट की उस निगरानी सूची में था जिसमें ईरानी तेल और गैस ले जाने वाले जहाजों का नाम है. एक और जहाज ने खोर अल जुबैर में बंदरगाह पहुंचने का दावा किया, लेकिन सैटेलाइट इमेज में वह वहां नहीं दिखा. चौथा जहाज, जो बार-बार मुंद्रा में डॉक करता है, अमेरिका के ऊर्जा विभाग की 2024 की रिपोर्ट में ईरानी पेट्रोलियम के निर्यातक के रूप में नामित किया गया है।

अडानी समूह ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को पूरी तरह से से खारिज किया है और कहा है कि एलपीजी व्यापार 'ऑपरेशनल रूप से महत्वपूर्ण नहीं' है—यह अडानी एंटरप्राइज़ेज की कुल 11.7 बिलियन डॉलर की वार्षिक आमदनी का सिर्फ 1.46% है।

समूह ने कहा कि वह सभी एलपीजी खरीद विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं से अनुबंध के ज़रिए करता है, ओएफएसी प्रतिबंध सूची में शामिल किसी कंपनी से व्यापार नहीं करता और शिपिंग का काम थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक कंपनियों के ज़रिए अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुरूप करवाता है।

वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट में जिन खेपों का उल्लेख किया गया है, उन पर प्रतिक्रिया देते हुए अडानी ने कहा कि यह एक नियमित वाणिज्यिक लेनदेन था, जिसे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक पार्टनर ने मैनेज किया, और दस्तावेजों में सोहर (ओमान) को माल का स्रोत बताया गया है। अडानी समूह ने यह भी कहा, 'हम इन जहाजों (जैसे SMS Bros/Neel) के मालिक, ऑपरेटर या ट्रैकर नहीं हैं और न ही हमने इन्हें अनुबंधित किया है, इसलिए हम इनकी किसी भी वर्तमान या अतीत की गतिविधियों पर टिप्पणी नहीं कर सकते।' समूह ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि एक प्रामाणिक आयातकर्ता की जो भी जिम्मेदारियां होती हैं, वे पूरी की गई हैं।

खीर भवानी मंदिर में महबूबा मुफ्ती ने की पूजा-अर्चना, बोलीं- बंदूकों से नहीं हो सकता मुद्दों का समाधान

स्वतंत्र प्रभात

जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने गंदेरबल में खीर भवानी मंदिर में पूजा-अर्चना की। खीर भवानी मेला कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण वार्षिक धार्मिक उत्सव है। यह गंदेरबल जिले के तुल्ला मुल्ला गांव में खीर भवानी मंदिर में आयोजित किया जाता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीडीपी का मानना है कि जम्मू-कश्मीर में मुद्दों का समाधान बंदूकों से नहीं हो सकता। आतंकवाद इसका समाधान नहीं है। इसके लिए राजनीतिक प्रक्रिया होनी चाहिए। यह राजनीतिक प्रक्रिया तब तक हासिल नहीं हो सकती जब तक हमारे सभी कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस नहीं आ जाते।

इससे पहले पवित्र माता खीर भवानी मंदिर में आयोजित मेला खीर भवानी के शुभ अवसर पर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू-कश्मीर के लोगों, विशेष रूप से कश्मीरी पंडित समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। यह जीवंत त्योहार कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच स्थायी एकता, सद्भाव और साझा सांस्कृतिक विरासत का एक कालातीत प्रमाण है, जो दुनिया के सामने उनके अटूट बंधन को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मेला खीर भवानी सिर्फ़ एक धार्मिक आयोजन नहीं है; यह हमारी साझा विरासत और कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच अटूट बंधन का उत्सव है।

उन्होंने कहा कि यह त्यौहार हमें प्रेम, करुणा और एकता के मूल्यों की याद दिलाता है जो कश्मीर की आत्मा को परिभाषित करते हैं। मैं अपने कश्मीरी पंडित भाइयों की अपने वतन में सम्मानजनक वापसी और हमारी घाटी में स्थायी शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। देवी खीर भवानी को समर्पित एक वार्षिक उत्सव मेला खीर भवानी, कश्मीरी पंडितों के लिए सबसे प्रतिष्ठित आध्यात्मिक आयोजनों में से एक है,

जो तुल्लामुल्ला में पवित्र मंदिर में हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। दशकों से इस क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद, यह त्योहार आशा, लचीलापन और सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक बना हुआ है। यह कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच गहरे संबंधों का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जो अशांत समय में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं और धार्मिक और सांस्कृतिक विभाजनों से परे एकता का प्रदर्शन किया है।

आप होंगे कमल हासन, लेकिन...कर्नाटक हाईकोर्ट ने जमकर लगाई फटकार

स्वतंत्र प्रभात

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अभिनेता कमल हासन को फटकार लगाई है। उन्होंने राज्य में अपनी फिल्म ठग लाइफ की रिलीज के लिए कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की थी। कन्नड़ भाषा पर कमल के बयान के विरोध के कारण कर्नाटक में फिल्म की रिलीज पर संकट मंडरा रहा है। हालांकि, अभिनेता ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। बता दें कि कमल हासन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स समेत अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे ठग लाइफ की रिलीज का विरोध न करें। अभिनेता के वकील ने दलील दी कि बयान को गलत संदर्भ में लिया गया है और कमल हासन द्वारा लिखित जवाब कोर्ट में पेश किया। लाइव लॉ के अनुसार, बेंच ने कहा कि अगर यह माफ़ी का जवाब है, तो हम इसे स्वीकार करेंगे। इसमें माफ़ी की कोई बात नहीं है। आप कमल हासन हों या कोई और, आप जनता की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा सकते। 'कन्नड़ तमिल से निकला है' वाले अपने बयान पर दिग्गज अभिनेता को फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट की बेंच ने कहा, 'इस देश का विभाजन भाषाई आधार पर है। एक सार्वजनिक व्यक्ति ऐसा बयान नहीं दे सकता। इसके कारण क्या हुआ है? अशांति, वैमनस्य। कर्नाटक के लोगों ने केवल माफ़ी मांगी थी। अब आप सुरक्षा मांगने आए हैं। आपने किस आधार पर बयान दिया है? क्या आप इतिहासकार या भाषाविद् हैं? आपने किस आधार पर बात की? आप फिल्म का महत्व जानते हैं, कहते हैं कि यह मणिरत्नम द्वारा बनाई गई है, लेकिन आप बयान नहीं दे सकते।

कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स (केएफसीसी) द्वारा फिल्म के बहिष्कार की घोषणा के बाद कमल ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जब तक कि अभिनेता अपने हालिया बयानों के लिए

सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांग लेते। चेन्नई में एक प्रचार कार्यक्रम के दौरान की गई टिप्पणी ने कन्नड़ समर्थक संगठनों की ओर से व्यापक प्रतिक्रिया को जन्म दिया और राजनीतिक विवाद को जन्म दिया। केएफसीसी के अध्यक्ष एम. नरसिम्हालु ने चैंबर के रुख को दोहराया। नरसिम्हालु ने कहा, 'कमल हासन को अदालत जाना चाहिए। हमने कुछ भी अवैध नहीं किया है। लेकिन हम कर्नाटक में ठग लाइफ की स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं देंगे, जब तक कि वह माफी नहीं मांगते।

संक्षिप्त ख़बरें

विद्युत ट्रांसफार्मर में हुई स्पार्किंग की चपेट में आकर किसान की मौत

लखीमपुर खीरी। अमीरनगर क्षेत्र के ग्राम हजरत पुर निवासी बग्गा सिंह पुत्र निरंजन सिंह ने थाना मोहम्मदी पर दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि कल रविवार की शाम लगभग 5 बजे उसका पुत्र कुलदीप सिंह (34) वर्ष पुत्र बग्गा सिंह अपने खेत में खड़ी धान की फसल में घास उखाड़ रहा था तभी खेत के पास में लगे बिद्युत ट्रांसफार्मर में विधुत फाल्ट होने से चिंगारीयां निकलने लगीं, जिसकी चपेट में आकर कुलदीप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई।मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। पोस्टमार्टम के पश्चात् आज शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मृतक के परिवार में पत्नी,व दो नाबालिग बच्चों में एक बेटा और एक बेटी है। मृतक के पिता का रो-रो के बुरा हाल है मृतक के पिता ने बताया की मेरे दो बेटे और एक बेटी थी जिसमें कुलदीप सिंह सबसे बड़ा बेटा था। उसी के कंधों पूरी घर की जिम्मेदारी थी।

आपत्तिजनक फोटो और भद्दे कमेंट्स सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के कुर्मी सराय गांव के तीन ग्रामीणों ने गांव के ही एक युवक पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फोटो और अभद्र टिप्पणियां वायरल करने का आरोप लगाया है। पीड़ितों ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर सौंपी और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि आरोपी युवक वर्तमान में मुंबई में रह रहा है और गांव से पुरानी रंजिश के चलते उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहा है।ग्रामीण विनोद कुमार पटेल, अशोक पटेल और ऋषभ पटेल ने बताया कि जब उन्होंने इस संबंध में आरोपी के परिजनों से बात करने की कोशिश की, तो आरोपी के परिवार के सदस्य भी गाली-गलौज और मारपीट पर उतारू हो गए। इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर

रेगुलर डिग्री के लिए बारा में आज तक नहीं खुला कोई शिक्षण संस्थान इंटर पास करने के बाद छात्र-छात्राएं प्राइवेट ग्रेजुएशन करने को मजबूर।

स्वतंत्र प्रभात

बारा (प्रयागराज)। प्रयागराज जनपद के बारा तहसील में आज भी इंटर के बाद जब छात्र एवं छात्राएं परीक्षा पास कर लेते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा धर्म संकट उत्पन्न होता है कि आगे की शिक्षा कैसे जारी रखी जाए। राज्य में कई सरकार आई, शिक्षा विभाग के नियम बदले यहां तक की कई विधायकों और लोकल नेताओं ने हवा भरी की छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए डिग्री कॉलेज जिससे यहां पर निवास करने वाले छात्र एवं छात्राओं को ग्रेजुएशन करने के लिए रेगुलर क्लास चलने वाले कॉलेज का निर्माण करवाया जाएगा लेकिन विद्यार्थियों के किस्मत में केवल झूठे हवा हवाई वादे ही आए। आज आधुनिकता के युग में शंकरगढ़ क्षेत्र उस जगह पर पहुंच चुका है जहां छात्रों को उच्च शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई डिग्री कॉलेज महाविद्यालय आज तक नहीं बन पाया है। मजबूरन छात्र एवं छात्राएं ग्रेजुएशन करने के लिए प्राइवेट दूर दराज के डिग्री कॉलेज से फॉर्म भरकर 3 साल की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। छात्रों की मजबूरी है की कक्षाएं ना चलने के कारण जब सेमेस्टर एग्जाम आते हैं तो प्राइवेट डिग्री कॉलेज द्वारा गरीब एवं मजबूर छात्रों से प्राइवेट संस्थानों द्वारा नकल कराने और डिग्री देने के नाम पर भारी भरकम वसूली की जाती है। और शैक्षणिक ज्ञान के नाम पर उन्हें कुछ नहीं प्राप्त होता है। नेताओं की फौज इतनी है कि चुनाव के वक्त और सोशल मीडिया में बारा विधानसभा को लगता है सब कुछ न्योछावर कर देंगे। लेकिन जब विधानसभा और शंकरगढ़ क्षेत्र की शिक्षा पर सवाल आता है तो विधायक से लेकर सांसद तक नतमस्तक होते हुए दिखाई पड़ते हैं। आखिर क्या वजह है कि

आज तक शंकरगढ़ क्षेत्र के गरीब छात्र-छात्राओं को जिनके पास आर्थिक समस्या है उनके लिए सुचारू रूप से कक्षाएं चलने वाला डिग्री कॉलेज आज तक नहीं खोला गया। सबसे बड़ी समस्या छात्राओं को हो रही है जिनके माता-पिता चाह कर भी अपनी लड़कियों को बाहर नहीं भेज पा रहे हैं। यही कारण है कि छात्राएं मजबूरन प्राइवेट ग्रेजुएशन करने के लिए बाध्य हो रही है। लेकिन कई दशक बीत जाने के बाद भी आधुनिकता के जमाने की बात करने वाले नेताओं के मन में एक बार भी यह ख्याल नहीं आया कि क्षेत्रीय बच्चों की शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था की जाए यह सवाल आज भी लोगों के मन में पीड़ा बनकर उभर रहा है।

मुजफ्फरनगर में मदरसे के मौलवी ने नाबालिग छात्रा से किया दुष्कर्म

स्वतंत्र प्रभात

प्रयागराज। मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के सुभाष नगर स्थित एक मदरसे में पढ़ने वाली 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. मदरसे के मौलवी ने ही किशोरी के साथ गंदा काम किया. पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी मौलवी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।उत्तराखंड के हरिद्वार की रहने वाली एक विधवा ने कुछ समय पहले अपनी 2 नाबालिग बेटियों का दाखिला सुभाष नगर के एक मदरसे में कराया था. इनमें से एक 15 वर्षीय बेटी कक्षा छह में पढ़ती है. आरोप है कि 5 अप्रैल 2025 को मौलवी सद्दाम हुसैन ने मदरसे में ही छात्रा के साथ दो बार दुष्कर्म किया, फिर छात्रा को धमकी दी कि वह इस बारे में किसी को न बताए. अन्यथा अंजाम बुरा होगा।

डर के कारण छात्रा ने कुछ दिनों तक घटना

को छिपाए रखा. लेकिन कुछ दिन पहले छात्रा ने अपनी मां को घटना की जानकारी दी. इसके बाद पीड़ित की मां ने नई मंडी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी मौलवी सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। सीओ नई मंडी रुपाली राय ने बताया कि आरोपी ने दो साल पहले अपना मदरसा खोला था. फिलहाल पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है. मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. साथ ही आरोपी का चालान भी कर दिया गया है।

भाजपा सरकार की 'हर घर जल' योजना अब 'हर घर छल' बन चुकी है- विनय पटेल

● भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी भाजपा सरकार- लखीमपुर में ?5.31 करोड़ की पानी की टंकी गिरना जनविरोधी शासन का प्रतीक विनय पटेल

लखीमपुर खीरी। सोमवार को अवध प्रान्त अध्यक्ष विनय पटेल ने योगी सरकार पर हमलावार होते हुए कहा कि सीतापुर के चौंका बेहेमा गांव में जल जीवन मिशन के तहत ?5.31 करोड़ की लागत से बनी पानी की टंकी का ढह जाना भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार और लापरवाही की जीती-जागती मिसाल है। यह टंकी, जो जनवरी 2024 में चालू हुई थी और आठ गांवों के 5,000 से अधिक लोगों की जल आपूर्ति का एकमात्र स्रोत थी, मात्र दो महीने के उपयोग के बाद ही धराशायी हो गई!

उन्होंने आगे कहा कि यह हादसा नहीं, बल्कि भाजपा सरकार की भ्रष्टाचार-प्रेरित नीतियों का परिणाम है। जब 5.31 करोड़ की लागत से बनी संरचना दो महीने में ही गिर जाए, तो यह स्पष्ट है कि निर्माण में घटिया सामग्री और भ्रष्टाचार की भूमिका है। विनय पटेल ने शेरपुर

गांव का दौरा किया उस दौरान गांव वालों ने बताया की पानी की टंकी बनाते वक्त कई कमियां पाई गई इसके बारे में शासन प्रशासन को बताया भी गया। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आगे कहा कि भाजपा सरकार की 'हर घर जल' योजना अब 'हर घर छल' बन चुकी है। जनता के पैसे से बने ढांचे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं, और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। इस अवसर पर पंचायत प्रकोष्ठ अध्यक्ष विनय कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण वर्मा, जिला प्रभारी आशुतोष श्रीवास्तव,जिला अध्यक्ष हाशिम सिद्दीकी, जिला उपाध्यक्ष निर्मल सिंह, जिला उपाध्यक्ष रिजवान जिला उपाध्यक्ष सतनाम जी जिला कोषाध्यक्ष अनुराग रस्तोगी, जिला सचिव संदीप पाल जिला अध्यक्ष श्रम

जलालपुर में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली, गिरफ्तार

● आरोपी के पैर में लगी गोली, तमंचा व बिना नंबर की बाइक बरामद

स्वतंत्र प्रभात

जौनपुर। पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना जलालपुर पुलिस टीम द्वारा एक शातिर अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक देशी तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, बिना नंबर प्लेट की बाइक को बरामद किया गया।

थानाध्यक्ष त्रिवेणी सिंह ने बताया कि मय हमराह हेड कांस्टेबल पियूष सिंह, अजय चौहान, चालक दीपक मौर्या के साथ बीती रात्रि में एसआई रोहित राज यादव, एसआई रामअवतार यादव, कांस्टेबल खुर्शीद आलम, श्यामप्रकाश के साथ वाराणसी से रेहटी गांव के पास हाईवे पर वाराणसी से लखनऊ जाने वाली लेन पर चेकिंग कर रहे थे।

बदमाश को पुलिस ने टॉर्च की रोशनी से रोकने का दिया इशारा

इसी दौरान वाराणसी की तरफ से एक बाइक तेज गति से आती दिखी, जिसे पुलिस ने टॉर्च की रोशनी से रोकने का इशारा किया। इस पर पुलिस को देख कर बदमाश हाईवे लेन से सटे बगीचे की तरफ मुड़कर भागने लगा। टीम द्वारा जब पीछा किया गया तो वह बगीचे से छितौना लोहगाजर मार्ग की तरफ भागने का प्रयास करने लगा।

बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग

इस दौरान अनियंत्रित होकर मार्ग के किनारे फिसलकर गिर गया। पुलिस को आते देख पकड़े जाने के डर से बदमाश ने पुलिस को लक्ष्य करके जान से मारने की नियत से फायरिंग झोंक दी। इस पर पुलिस द्वारा आत्मसपर्पण की चेतावनी देने के बाद भी नहीं माना तो थानाध्यक्ष त्रिवेणी सिंह

द्वारा फायर किया गया। इसमें बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी और जमीन पर गिरकर कराहने लगा। घायल बदमाश की पहचान किशन सरोज उर्फ भोथू पुत्र रामचन्द्र सरोज निवासी सैदपुर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर उम्र करीब 20 वर्ष के रूप में हुई। घायल अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में लेकर प्राथमिक इलाज हेतु सीएचसी रेहटी भेजा गया। वहीं अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बदमाश पर कई थानों में दर्ज है आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार बदमाश का कई थानों में आपराधिक इतिहास है। थाना जीआरपी, थाना चोलापुर जनपद कमिश्नरेट वाराणसी, थाना शिवपुर जनपद कमिश्नरेट वाराणसी, गैंगस्टर एक्ट थाना शिवपुर जनपद कमिश्नरेट वाराणसी, आर्म्स एक्ट

लाल आतंक के गढ़ में लहरा रहा तिरंगा

चार दशक से ज्यादा समय तक नक्सलवाद का शिकार रहे छत्तीसगढ़ का बस्तर जिले को अब वामपंथी उग्रवादियों (एलडब्ल्यूई) जिले की सूची से बाहर कर दिया गया है। अपने आप में ये बड़ी खबर है। दरअसल मोदी सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक भारत पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो जाए। गृह मंत्री अमित शाह भी कई बार सार्वजनिक मंच से इस बात को दोहरा चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगस्त 2024 और दिसंबर 2024 में छत्तीसगढ़ के रायपुर और जगदलपुर आए थे। वे यहां अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने अलग-अलग मंचों से नक्सलियों को चेताते हुए कहा था कि हथियार डाल दें। हिंसा करोगे तो हमारे जवान निपटेंगे। वहीं उन्होंने एक डेडलाइन भी जारी की थी कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। शाह के डेडलाइन जारी करने के बाद से बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन काफी तेज हो गए हैं।

नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई है। इसकी शुरुआत स्थानीय जमींदारों के खिलाफ विद्रोह के रूप में हुई, जिन्होंने भूमि विवाद को लेकर एक किसान की पिटाई की थी। यह आंदोलन जल्द ही पूर्वी भारत के छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे कम विकसित क्षेत्रों में फैल गया। वामपंथी उग्रवादियों (एलडब्ल्यूई) को दुनिया भर में माओवादी और भारत में नक्सलवादी के नाम से जाना जाता है। वे सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत सरकार को उखाड़ फेंकने और माओवादी सिद्धांतों पर आधारित साम्यवादी राज्य की स्थापना की वकालत करते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल राज्यों को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित माना जाता है। देश में भाजपा सरकार बनने के बाद 2015 में नक्सलवाद के खिलाफ विशेष अभियान चलाने की नीति बनाई गई। तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 सूत्रीय समाधान एक्शन प्लान बनाया। इसमें नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई और नक्सली इलाकों में विकास के काम एक साथ किए गए। नक्सलियों के खिलाफ राज्य सरकारों के विशेष बल, केंद्रीय सुरक्षा बलों, पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की। इससे नक्सली घटनाओं में जबरदस्त कमी आयी।

2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जिसे भारत की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती कहा था, वही नक्सलवाद अब खत्म होता दिख रहा है। नक्सलियों ने नेपाल के पशुपति से आंध्र प्रदेश के तिरुपति तक एक रेड कॉरिडोर स्थापित करने की योजना बनाई थी। 2013 में लगभग 126 जिलों में नक्सली सक्रिय थे। वर्तमान में नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर 6 हो गई। इनमें छत्तीसगढ़ के चार जिले- बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा, झारखंड का एक जिला- पश्चिमी सिंहभूम और महाराष्ट्र का एक जिला- गढ़चिरौली शामिल है।

वर्ष 2025 में सुरक्षाबलों के ऑपरेशन में अब तक 287 नक्सली मारे जा चुके हैं। वहीं 865 ने समर्पण किया है और 830 गिरफ्तार हुए हैं। गत 21 मई को सुरक्षाबलों ने अबूझमाड़ में डेढ़ करोड़ के इनामी नंबला केशव उर्फ बसवराज को मार गिराया था। वह तीन दशक से सक्रिय था। इसे नक्सलियों का हाफिज सईद भी कहा जाता है। नक्सलियों के सरदार बसवा राजू के ढेर होने के बाद माओवादियों का हौसला पस्त हो गया है। इस बड़े एनकाउंटर के बाद दक्षिण बस्तर डिवीजन के 4 हार्डकोर नक्सलियों सहित 18 माओवादियों ने सरेंडर किया था। इसी तरह बीजापुर में 32 और तेलंगाना में 86 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। बासव राजू की मौत के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर लिखा था कि महासचिव स्तर के बड़े नक्सली नेता को मारा गया है। इस कामयाबी को हासिल करने वाला 'ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट' भी सुर्खियों में है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते वर्ष 2025 में अब तक 90 नक्सली मारे जा चुके हैं, 104 को गिरफ्तार किया गया है और 164 ने आत्मसमर्पण किया है। वर्ष 2024 में 290 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज़ किया गया था, 1090 को गिरफ्तार किया गया और 881 ने आत्मसमर्पण किया था। अभी तक कुल 15 शीर्ष नक्सली नेताओं को न्यूट्रलाइज़ किया जा चुका है। वर्ष 2004 से 2014 के बीच नक्सली हिंसा की कुल 16,463 घटनाएं हुई थीं, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में 2014 से 2024 के बीच हिंसक घटनाओं की संख्या 53 प्रतिशत घटकर 7,744 रह गई है। इसी प्रकार, सुरक्षाबलों की मृत्यु की संख्या 1851 से 73 प्रतिशत घटकर 509 रह गई और नागरिकों की मृत्यु की संख्या 70 प्रतिशत की कमी के साथ 4766 से 1495 रह गई है।

वर्ष 2014 तक कुल 66 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन थे जबकि मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में इनकी संख्या बढ़कर 612 हो गई है। इसी प्रकार, 2014 में देश में 126 ज़िले नक्सल प्रभावित थे, लेकिन 2024 में सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या घटकर मात्र 12 रह गई है। पिछले 5 वर्षों में कुल 302 नए सुरक्षा कैंप और 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड बनाए गए हैं। नक्सली हिंसा में 2010 में 720 नागरिक मारे गए। 2024 में मरने वालों की संख्या घटकर 131 हो गई। नक्सली हिंसा में 2010 में 1005 नागरिक और सुरक्षा बल मारे गए। 2024 में 150 नागरिक और सुरक्षा बल मारे गए। यानि कि मरने वालों की संख्या में 85 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। नक्सली आर्थिक ढांचे जैसे कि रेलवे प्रॉपर्टी, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की इकाइयों, टेलीफोन एक्सचेंज, मोबाइल टॉवर, सड़क, स्कूल को निशाना बनाते रहे हैं। पर पिछले कुछ साल से इन घटनाओं में कमी आई है। 2010 में हमले की ऐसे 365 मामले थे, जो 2024 में घटकर 25 रह गए।

पिछले एक दशक में मिली सफलता का श्रेय सुरक्षा रणनीति के साथ ही विकास योजनाओं में आई तेजी को भी जाता है। सरकार ने लक्षित विकास योजनाएं चलाई, जिनसे लोगों का भरोसा दोबारा जीता जा सका। सड़क और मोबाइल नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कामों ने स्थानीय लोगों के दिलों में जगह बनाई है। वहीं, 'रोशनी योजना' ने आदिवासी युवाओं को कौशल विकास और रोजगार प्राप्त करने में मदद की है।

केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वह उन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के दबाव में नहीं आएगी, जो बंदूक उठाने वाले माओवादी उग्रवादियों का समर्थन करते हैं। पिछले एक दशक से सरकार ने माओवाद के खिलाफ एक मजबूत और बहुआयामी रणनीति अपनाई है, जो अब काफी असरदार साबित हो रही है। गृह मंत्रालय की 2017 में शुरू की गई 'समाधान' रणनीति ने जमीन पर बड़ा फर्क डाला है। इसमें सुरक्षा संबंधी कार्ययोजना के साथ-साथ विकास से जुड़ी पहल भी शामिल है।

नक्सलियों के खिलाफ अभियान मोदी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। इस से पहले कोई सरकार ऐसी इच्छाशक्ति दिखा नहीं पाई। ध्यान इस बात का रखना होगा कि नक्सलवाद फिर सिर न उठा पाए, इसके लिए प्रभावित इलाकों में अगला चरण लोकोन्मुखी सरकार, भूमि अधिकार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आर्थिक उत्थान पर फोकस होना चाहिए। जमीनी लड़ाई में जीत केवल आधी सफलता है, अगला फोकस नक्सलियों के पुनर्वास और उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने पर होना चाहिए। जिस तरह मोदी सरकार नक्सली समस्या को खत्म काने क़ि दिशा मे तेज़ी से बाद रही है उम्मीद है क़ि वो 2026 में समस्या के स्थायी समाधान के साथ देश के सामने गर्व से खड़ीं होगी।

एमएसपी घोषणा सकारात्मक पहल तो चाकचोबंद खरीद व्यवस्था भी जरुरी

केन्द्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा खरीफ की बुवाई से पहले ही करने को किसानों के हित में सकारात्मक पहल के रुप में देखा जाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा एक तो समय पूर्व समर्थन मूल्यों की घोषणा की जा रही है वहीं दूसरी और भविष्य की रणनीति के तहत आवश्यकतानुसार उत्पादन बढाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी कदम बढ़ाये जा रहे हैं। सरकार द्वारा श्री अन्न को जहां अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने का सफल प्रयास किया गया है वहीं देश को दलहन और तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। 2027 तक दलहन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ सरकार आगे बढ़ रही है तो तिलहन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रयास किये जा रहे हैं। सरकार की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि आगामी खरीफ के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों में रामतिल के भावों में सर्वाधिक 820 रु. की बढ़ोतरी करते हुए 9537 रु. प्रति क्विंटल एमएसपी घोषित की गई है। इसी तरह से तिल की एमएसपी में 579 रु., सोयाबीन में 436 रु., सूरजमुखी में 441 रु. और मूंगफली की एमएसपी में 480 रु. की बढ़ोतरी की गई है। ठीक इसी तरह से उड़द में 400 रु. तो मूंग की एमएसपी में 86 रु. और अरहर की एमएसपी में 450 रु. की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह से बाजरा, रागी, ज्वार, कपास, धान आदि अन्य खरीफ फसलों की एमएसपी दरों में बढ़ोतरी की गई है।इसमें कोई दो राय नहीं कि जहां तक एमएसपी दरों की घोषणा की बात है सरकार की ईच्छा शक्ति पर किसी तरह का संदेह नहीं किया जा सकता है। मोदी सरकार के 2013-14 से 2025-26 तक के कार्यकाल की एमएसपी दरों में बढ़ोतरी निश्चित रुप से सकारात्मक दिषा में बढ़ता कदम माना जा सकता है। 2013-14 की तुलना में 226 प्रतिशत की बढ़ोतरी रागी के समर्थन मूल्य में की गई है। बाजरा में 122 प्रतिशत तो ज्वार की एमएसपी में 147 प्रतिशत तक की बढोतरी हो चुकी है। दलहन और तिलहन की खरीफ फसलों में भी 82 प्रतिशत से रामतिल में 172 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। सरकार का यह भी दावा है कि एमएसपी घोषणा करने से पहले सरकार ने फसलों की लागत के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा है और लागत से कहीं अधिक एमएसपी दर जारी की गई है। किसान आंदोलनों के दौरान सबसे अहम् मुद्दा एमएसपी को लेकर ही रहता आया है। सरकार एक और एमएसपी दरों में बढ़ोतरी और एमएसपी पर खरीद का दावा कर रही है और यह दावा एक हद तक सही भी है पर दूसरी और किसान नेताओं का यह कहना रहा है कि सरकार एमएसपी दरों की घोषणा के साथ ही एमएसपी पर खरीद की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। केन्द्र सरकार की और से एफसीआई और नेफैड एमएसपी खरीद के लिए नोडल संस्था है तो कपास की खरीद सीसीआई द्वारा की जाती है। राज्यों में एफसीआई व नेफैड के लिए खरीद सुविधा में राज्यों की सहकारी विपणन संस्थाएं प्रमुखता से सहभागी रहती है। खरीद की व्यवस्था को भी पारदर्शी और ऑनलाईन कर दिया गया है और रजिस्ट्रेशन से लेकर सीधे खातों में भुगतान तक की व्यवस्था ऑनलाईन की गई है। पर कहीं ना कही व्यवस्था में झोल अवश्य है। इसको यों समझा जा सकता है कि एक समय था तब सरकारी खरीद शुरु होने की घोषणा और लगभग 10 से 15 प्रतिशत उत्पादन की खरीद होते होते मण्डियों में भाव एमएसपी के आसपास आ जाते थे। इसका परिणाम यह होता था कि ना तो किसानों की नाराजगी रहती थी और ना ही अन्य कोई समस्या आती थी। पर आज खरीद व्यवस्था के पारदर्शी होने के बावजूद किसान अपने आप को ठगा महसूस करता है। इसका एक बड़ा कारण तो यह है कि बाजरा आदि की खरीद तो सरकार द्वारा किसी ना किसी बहानें टाली ही जाती है क्योंकि बाजरे की खरीद के बाद रखरखाव को लेकर संकट रहता है और सरकार का मानना है कि उसे नुकसान अधिक होता है क्योंकि खरीदा हुआ बाजरा जल्दी खराब हो जाता है। वहीं दूसरी और व्यवस्था को लाख पारदर्शी और जबावदेह बनाने के बावजूद बिचौलियें इस व्यवस्था का भरपूर लाभ उठाते देखे जा रहे हैं। कहीं कहीं तो खरीद केन्द्रों पर जितनी मात्रा में खरीद हो रही है वह उस क्षेत्र में उत्पादित पैदावार से भी अधिक हो जाती है। इसके साथ ही किसानों की तात्कालीक आवश्यकताओं के चलते आड़तियों पर निर्भरता के कारण भी किसान का लाभ आड़तियां ले जाता है। हांलाकि यह व्यवस्था का ही दोष माना जा सकता है। होना तो यह चाहिए कि जिन फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार द्वारा की जाती है उन फसलों के तैयार होकर मण्डियों में आने से पहले ही सरकार को खरीद की आवश्यक तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए। खरीद के लिए खरीद केन्द्र की स्थापना, तुलाई ढुलाई की व्यवस्था, बारदाना, ट्रांसपोर्टेशन, भण्डारण, भुगतान की आवश्यक व्यवस्था, बैंकों से भुगतान आदि की व्यवस्था, खरीद केन्द्रों पर पीने के लिए पानी आदि की व्यवस्था सहित आवश्यक सभी तैयारियां सुनिश्चित हो जानी चाहिए। इसके साथ ही आज सरकार के पास उत्पादन के सारे डेटा उपलब्ध होते हैं ऐसे में संभावित खरीद का आकलन भी सुनिश्चित हो जाना चाहिए। सरकार द्वारा पूर्व में ही यह घोषणा कि इतनी मात्रा में ही खरीद की जाएगी तो इससे राजनीति के अधिक अवसर उत्पन्न हो जाते हैं और अनावश्यक भ्रम के हालात बन जाते हैं। ऐसे हालात से बचा जाना जरुरी हो जाता है।

दैनिक राशिफल

ज्योतिष सेवा केन्द्र लखनऊ
डॉ.कौशलेन्द्र पाण्डेय जी

मेष

आज तीर्थयात्रा हो सकती है। सत्संग का लाभ मिलेगा। धन प्राप्ति सुगम होगी। वरिष्?ठजनों का सहयोग मिलेगा। नवीन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए दिन अच्छा होने की संभावना है। प्रेम-प्रसंग में सफलता मिलेगी। परिवार में मेल-मिलाप बढ़ेगा। अधिकारी वर्ग में महत्व बढ़ेगा।

वृष

आज विवाद व जल्दबाजी से बचें। पार्टी व पिकनिक का आनंद मिलेगा। बौद्धिक कार्य सफल रहेंगे। प्रसन्नता रहेगी। स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें। अधूरे काम समय से पूरे होने के योग हैं। नए कार्यों से लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। धन का संग्रह होगा।

मिथुन

आज सुख के साधन जुटेंगे। भूमि व भवन की योजना बनेगी। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा। संतान की प्रगति होगी। व्यापार-व्यवसाय में प्रगतिकारक वातावरण का सृजन होगा। पारिवारिक स्थिति आनंददायक रहेगी। मन प्रफुल्लित रहेगा।

कर्क

आज संतान पक्ष की चिंता रहेगी। चोट व दुर्घटना से बचें। लेन-देन में सावधानी रखें। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। खर्च का बोझ बढ़ेगा। किसी पर अत्यधिक भरोसा न करें। व्यापार, नौकरी में अड़चनें आने से मनोबल में कमी आ सकती है।

सिंह

आज प्रेम में सफलता मिलेगी। प्रयास सफल रहेंगे। रुके कार्यों में गति आएगी। मान-सम्मान मिलेगा। धनार्जन होगा। प्रसन्नता रहेगी। पारिवारिक सुख एवं पत्नी के सहयोग से मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। किसी से बहस न करें। काम-धंधे में सफलता के शुभ संकेत हैं।

कन्या

आज लेनदारी वसूल होगी। यात्रा मनोरंजक रहेगी। लाभ के अवसर मिलेंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा। प्रसन्नता रहेगी। राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष लाभ का योग है। आर्थिक उन्नति होगी। सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति करेंगे। ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी।

तुला

आज प्रेम-प्रसंग में सफलता मिलेगी। बाहर सहायता से काम होंगे। प्रसन्नता रहेगी। संतान के संबंध में संतोष रहेगा। व्यावसायिक अथवा आजीविका संबंधी समस्या का समाधान हो सकेगा। पुरुषार्थ का पूर्ण फल मिलेगा। थकान रहेगी। शत्रु भय रहेगा।

वृश्चिक

आज यात्रा में सावधानी रखें। विवाद को बढ़ावा न दें। दुःखद समाचार मिल सकता है। दौड़धूप अधिक होगी। वाणी पर संयम रखें। विरोधियों से सावधान रहें। परिवार की परेशानी का हल संभव है। भागीदारी के कामों में सफलता मिलेगी।

धनु

आज अतिथियों का आवागमन होगा। शुभ समाचार प्राप्त होंगे। वाणी पर नियंत्रण रखें। आत्मसम्मान बना रहेगा। सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभा सकेंगे। पारिवारिक सुख-शांति बरकरार रहेगी। जोखिम के कार्यों से दूर रहें। यात्रा होगी।

मकर

आज कुसंगति से बचें। फालतू खर्च होंगे। लेन-देन में सावधानी रखें। जोखिम व जमानत के कार्य बिलकुल न करें। संतान की गतिविधियों पर नजर रखना होगी। कामकाज का बोझ बढ़ने से व्यापार पर विपरीत असर हो सकता है। वाद-विवाद से दूर रहें।

कुंभ

आज घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। नई योजना बनेगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। रुके कार्यों में गति आएगी। माता के स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना आवश्यक। पुराने रुके कामों, लेनदेन में सफलता की संभावना है। रोमांस में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को शिक्षा में उपलब्धि हासिल होने के योग हैं।

मीन

आज अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। जोखिम उठाएं। यात्रा मनोरंजक रहेगी। प्रसन्नता रहेगी। धनार्जन होगा। सोच-समझकर कार्य करना लाभप्रद रहेगा। पुरुषार्थ सफल होगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखना चाहिए। व्यापार में नवीन प्रस्ताव मिलेंगे।

संपादकीय

PM मोदी ने पाकिस्तान को दोटूक कहा कि भारत अब आतंकवादियों के जरिए छद्म युद्ध बर्दाश्त

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को दोटूक कहा है कि भारत अब आतंकवादियों के जरिए छद्म युद्ध बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि अब आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाएगा। अगर उधर से गोली चली तो जवाब गोले से दिया जाएगा। पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, उन्होंने हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया है। आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को भी चुनौती दी है। यह चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है। यह भी वास्तविकता है कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन बन गया है। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया है। यह भी दुखद है कि ऑपरेशन सिंदूर पर देश के भीतर खूब सियासत हो रही है। आरोपों-प्रत्यारोपों के बीच सीडीएस अनिल चौहान ने पाकिस्तान के फर्जी नैरेटिव का पूरी दुनिया के सामने भांडा फोड़ कर रख दिया है। चार दिन चले युद्ध के बाद पाकिस्तान ने दुनियाभर में अनर्गल प्रचार किया। पाकिस्तान के दावों को पूरी तरह से नकारते हुए सीडीएस अनिल चौहान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को पूरी तरह से फर्जी करार दिया कि भारत और पाकिस्तान परमाणु ताकत के इस्तेमाल के करीब थे। जहां तक विमानों को गिराये जाने का संबंध है सीडीएस अनिल चौहान ने यह पहली बार स्वीकार किया कि भारत के कुछ लड़ाकू विमानों को क्षति उठानी पड़ी है। सैन्य कार्रवाई के दौरान क्षति होना तय होता है।

प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रेलियन इंपीरियल फोर्स, ब्रिटिश सेना, फ्रांस, इटली, रूस, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीत हासिल की थी। दूसरे विश्व युद्ध में भी अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, चीन, सोवियत संघ और फ्रांस सेना ने जीत हासिल की थी। यद्यपि दोनों युद्धों में जर्मनी, आस्ट्रो-हंगरी साम्राज्य, ओटोमन सम्राज्य तथा इटली आदि को पराजय का सामना करना पड़ा लेकिन इन विनाशकारी युद्धों में लाखों सैनिक मारे गए और 9 करोड़ से अधिक नागरिक मारे गए, दोनों पक्षों का बहुत नुक्सान हुआ। सीडीएस अनिल चौहान ने पश्चिमी मीडिया समूहों की ओर से 6 विमान गिराये जाने की बात को भी पूरी तरह से निराधार बताया लेकिन यह भी कहा कि भारतीय सेना ने रणनीति बदलकर अपने सैन्य कौशल से पाकिस्तान को काफी नुक्सान पहुंचाया। कौन नहीं जानता हमारे रक्षा-कवच 'एस-400 सुदर्शन चक्र' ने पाकिस्तान हमलों को नाकाम कर दिया। पंजाब, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान के सीमावर्ती शहरों और गुजरात में कच्छ-भुज को निशाना बनाया गया था। यह टकराव घंटों जारी रहा। पाकिस्तान ने मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट से हमले किए लेकिन हमारे रक्षा कवच अभेद्य साबित हुए और दुश्मन के हमलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों के साथ-साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। उसके तमाम हमले विनष्ट कर दिए गए और उसका आक्रमण नाकाम साबित हुआ। पाकिस्तान के करीब 50 ड्रोन हवा में ही चिंदी-चिंदी कर दिए गए। राजस्थान के जैसलमेर में 70 मिसाइलें और जम्मू में 8 मिसाइलें मार गिराई। यही नहीं, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के दो जेएफ-17 और दो एफ-16 लड़ाकू विमानों को जमीन सुंघा दी। जेएफ चीनी और एफ अमरीकी जेट विमान हैं। पाकिस्तान ने जम्मू, ऊधमपुर, पठानकोट, जैसलमेर आदि शहरों में वायुसेना के आधारों को नष्ट करने की मंशा से कई हमले किए लेकिन सभी नाकाम हुए। भारतीय सेनाओं ने पलटवार कर लाहौर, कराची, पेशावर, सियालकोट और राजधानी इस्लामाबाद तक पाकिस्तान को थर्रा और दहला दिया। रावलपिंडी में सेना मुख्यालय को फिलहाल बख्शा गया है लेकिन वहां ड्रोन से हमले जरूर किए गए हैं। रावलपिंडी का स्टेडियम तहस-नहस कर दिया गया है। इन शहरों में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान का 'अवाक्स सिस्टम' बर्बाद कर दिया गया है। पाकिस्तान का 'रडार सिस्टम' भी विनष्ट कर दिया गया। भारतीय नौसेना के युद्धपोत 'आईएनएस विक्रांत' ने पाकिस्तान की व्यावसायिक-आर्थिक राजधानी कराची को दहला दिया। पाकिस्तान के 9 एयरबेस तबाह किये गये।

समूचा भारत सेना के शौर्य पराक्रम और प्रहारों की प्रशंसा कर रहा है। यह दुखद ही है? कि विपक्ष कांग्रेस और कुछ अन्य दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष मानसून सत्र में अपने सारे सवाल उठा सकता है। तो फिर विपक्ष संसद के विशेष सत्र की मांग क्यों कर रहा है। मानसून सत्र शुरू होने में कोई ज्यादा समय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह लगातार विपक्ष द्वारा गढ़े जा रहे नैरेटिव का जवाब दे रहे हैं। देशवासियों का भरोसा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार पर है तो विपक्ष को अनर्गल बयानबाजी से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। विपक्ष को पश्चिमी मीडिया के राग के साथ अपना राग नहीं अलापना चाहिए। ऐसी व्याख्याएं नहीं की जानी चाहिए जिससे दुश्मन को फायदा हो। बेहतर यही होगा कि ऑपरेशन सिंदूर पर सियात बंद कर दी जाए। सिंदूर ऐसा प्रतीक है जिसने देश के हर नागरिक को भावुक बना दिया है। विपक्ष सरकार के साथ मिलकर पाकिस्तान को आतंकवादी देश करार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाए तभी विपक्ष की छवि बचेगी।

बड़ी उम्मीद के साथ जनता चुनती है अपना प्रतिनिधि

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी जनता है। यही जनता हर पाँच वर्ष में अपने हाथों में भविष्य की बागडोर सौंपने का निर्णय करती है। वह मतदाता, जो कड़ी धूप हो या बारिश, हर मुश्किल को पार कर मतदान केंद्र तक पहुँचता है, वह केवल एक बटन नहीं दबाता वह अपने सपनों, अपनी उम्मीदों, अपनी पीड़ाओं और आकांक्षाओं को एक प्रतिनिधि को सौंप देता है। यह प्रतिनिधि संसद या विधानसभा में जाकर उसका स्वर बनेगा, उसकी लड़ाई लड़ेगा, उसकी समस्याओं को नीति में बदलने की दिशा में प्रयास करेगा, ऐसा विश्वास लेकर मतदाता अपने जनप्रतिनिधि को चुनता है। परंतु यह विश्वास कई बार टूटा हुआ महसूस होता है। जिस संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जहाँ जनभावनाओं को स्वर और समाधान मिलना चाहिए, वहाँ अक्सर कई सीटें खाली दिखाई देती हैं। जब देश के किसी कोने से कोई गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा अपनी बात कहने के लिए सीधे पहुँच नहीं सकता, तब उसे लगता है कि उसका प्रतिनिधि संसद में बैठेगा और उसकी पीड़ा को वहां उठाएगा। लेकिन जब वही प्रतिनिधि बार-बार संसद की कार्यवाही से अनुपस्थित पाया जाता है, ज़रूरी बहसों में भाग नहीं लेता, जब उसका नाम प्रश्न पूछने वालों की सूची में भी दिखाई नहीं देता, तो जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं है। यह एक सतत जिम्मेदारी है, जो चुनाव के परिणाम आने के बाद और भी गंभीर हो जाती है। एक सांसद का कार्य उसके शपथ लेने के साथ शुरू होता है, समाप्त नहीं। संसद में उसकी उपस्थिति, उसकी सक्रिय भागीदारी, उसके द्वारा पूछे गए प्रश्न, उसके उठाए गए मुद्दे, ये सब मिलकर यह तय करते हैं कि वह अपने कर्तव्यों के प्रति कितना संवेदनशील और सजग है। संसद केवल एक मंच नहीं, वह नीति-निर्माण का केंद्र है जहाँ बहसों, चर्चाओं और निर्णयों से देश की दिशा तय होती है। आज की राजनीति में अक्सर यह देखा गया है कि कई सांसद केवल मीडिया की चकाचौंध या सोशल मीडिया की पोस्टिंग तक ही सीमित रह जाते हैं। वे जनसभाओं और टीवी चैनलों पर जितने मुखर होते हैं, संसद में उतने ही मौन दिखाई देते हैं। कई बार ज़रूरी विधेयकों के दौरान संसद लगभग खाली रह जाती है, और कानून पारित हो जाते हैं बिना पर्याप्त चर्चा के। यह केवल एक संसदीय प्रक्रिया की त्रुटि नहीं, यह लोकतंत्र के मूल विचार जनप्रतिनिधित्व पर एक गहरा आघात है। ऐसा नहीं है कि सभी सांसद गैर-जिम्मेदार हैं। कई ऐसे भी हैं जो ईमानदारी और लगन से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। लेकिन जब बहुसंख्यक सांसद संसद को प्राथमिकता नहीं देते, तो उन कुछ गिने-चुने सांसदों की मेहनत भी छिप जाती है। और तब जनता का विश्वास पूरे तंत्र से डगमगाने लगता है। इस गिरती हुई जवाबदेही के लिए केवल सांसदों को दोष देना पर्याप्त नहीं है। जनता को भी सजग रहना होगा। प्रतिनिधियों से सवाल पूछना, उनके प्रदर्शन को देखना, यह जानना कि उन्होंने संसद में कितनी बार भाग लिया, किन विषयों पर बात की, अपने क्षेत्र की समस्याओं को कितनी गंभीरता से उठाया। यह सब मतदाता का कर्तव्य है। लोकतंत्र में अधिकार और जिम्मेदारी दोनों एक-दूसरे के पूरक होते हैं। यदि जनता जागरूक नहीं होगी, तो संसद में बैठने वाले अपने उत्तरदायित्व से और भी अधिक दूर होते जाएँगे। वक़्त आ गया है कि सांसदों को यह स्मरण कराया जाए कि संसद की हर कुर्सी लाखों-करोड़ों सपनों का भार उठाए बैठी है। वहाँ बैठना केवल एक विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। हर अनुपस्थिति, हर चुप्पी, हर टाले गए प्रश्न के पीछे कोई न कोई उम्मीद अधूरी रह जाती है। जो प्रतिनिधि चुनावों के समय रात-रात भर लोगों के बीच रहते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि असली लड़ाई संसद में होती है। वहीं से योजनाएँ बनती हैं, बजट पास होते हैं, कानून बनते हैं और वहीं से किसी किसान की ज़मीन सुरक्षित होती है, किसी छात्र की छात्रवृत्ति मिलती है, किसी बेरोजगार को नौकरी की उम्मीद मिलती है। संसद में हर एक आवाज़ मायने रखती है और हर एक अनुपस्थित सांसद लोकतंत्र की वह कड़ी है, जो अगर टूट जाए, तो पूरे तंत्र को अपंग बना सकती है। इसलिए समय की माँग है कि संसद की गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रतिनिधि सक्रिय रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करें। संसद में उनकी उपस्थिति केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि जनविश्वास का प्रतीक हो। वे यह न भूलें कि उन्हें चुनने वाली जनता अब जागरूक है, और आने वाले चुनावों में वह केवल वादों पर नहीं, उनके पूरे कार्यकाल की जवाबदेही पर निर्णय लेगी।लोकतंत्र विश्वास से चलता है और यह विश्वास तभी बना रह सकता है जब प्रतिनिधि अपने उत्तरदायित्व को समझें, निभाएँ और संसद को उस पवित्रता के साथ देखें, जैसी श्रद्धा के साथ जनता उन्हें चुनती है। क्योंकि जनता जब वोट डालती है, तो वह केवल सरकार नहीं चुनती । वह एक सपना चुनती है। और हर सपना एक जिम्मेदारी माँगता है। उस जिम्मेदारी को निभाना हर जनप्रतिनिधि का नैतिक, संवैधानिक और मानवीय धर्म है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सरकार को खरीफ श्री अन्न खासतौर से बाजरा आदि की खरीद की भी स्पष्ट नीति बनानी होगी अन्यथा श्री अन्न खासतौर से बाजरा को हम अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्म दिला रहे हैं वह जल्दी ही प्रभावित हो सकती है। सरकार को कोई ना कोई ऐसी स्पष्ट रणनीति बनानी होगी जिससे बाजरा उत्पादक किसान एमएसपी दर घोषित होने के बावजूद अपने आपकों ठगा महसूस ना कर सके। इसके लिए बाजार ताकतों को भी सक्रिय करना होगा ताकि बाजार में श्रीअन्न बाजरा आदि की मांग बढ़े और सरकारी खरीद ना होने की स्थिति में भी एमएसपी दर तो कम से कम उत्पादक किसान को बाजार में मिल सके। इसके लिए सरकार को इच्छाशक्ति के साथ आगे आना होगा। अब श्रीअन्न को प्रोत्साहित करने का हमारा दायित्व भी हो जाता है ऐसे में इस और अधिक गंभीरता से ध्यान देना होगा क्योंकि अभी तो बुवाई से फसल पकने तक का तीन से चार माह का समय सरकार के पास होगा। इस क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों को भी ठोस प्रयास करने होंगे ताकि इस समस्या का समाधान खोजा जा सके और अन्नदाता को उसकी मेहनत का पूरा पैसा मिल सके। देर सबेर सरकार को खरीद को सीमा में बांधने के स्थान पर स्थाई हल खोजना होगा ताकि एमएसपी व्यवस्था और अधिक किसान हितेषी हो सकें।

मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक रवि कुमार अवस्थी द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर परगना खैराबाद तहसील व जनपद -सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, हीवेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में छपे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोट:**-उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादो का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। **R.N.I NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0 -9511151254,** E-Mail :- news@swatantraprabhat .com

संक्षिप्त खबरें

देसी तमंचा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

तालगांव सीतापुर तालगांव कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत तालगांव पुलिस टीम के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्त को अवैध देसी असलहा के साथ गिरफ्तार किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ताल गांव कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बेनी राम पुल के निकट वाहन चेकिंग के दौरान मोहम्मद रियाज पुत्र शकील अहमद निवासी हिदायत नगर थाना कोतवाली लखीमपुर नगर को देसी तमंचा के साथ गिरफ्तार किया इस संबंध में ताल गांव कोतवाली प्रभारी दीपक राय ने बताया गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए न्यायालय भेजने की कार्यवाही की गई है। इस पुलिस टीम में मेहंदी पुरवा चौकी इंचार्ज ओवैस अली खान कांस्टेबल सौरभ कुशवाहा आदि शामिल रहे।

बच्चों ने लोकगीत और कविता पाठ किया

बिसवां (सीतापुर)। सोमवार को कंपोजिट विद्यालय जहांगीराबाद में आयोजित होने वाले समर कैंप में बच्चों को रोज की तरह योगाभ्यास और खेलकूद के बाद रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से पुस्तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके अलावा बच्चों के द्वारा लोकगीत व कविता का भी पाठ किया गया। विद्यालय में उपस्थित बच्चों को भाषा वृक्ष बनाना बताया गया। जिसके माध्यम से बच्चों को किसी भाषा को सीखने का क्या क्रम होता है इस बारे में जानकारी दी गई। अंत में बच्चों को जलपान का वितरण कर आज के समर कैंप का समापन किया गया।

बकरीद से पहले लहरपुर में पशु बाज़ार में रौनक 5 हज़ार से 40 हज़ार तक के बकरों की हुई ख़रीद- बिक्री

सीतापुर जनपद सीतापुर के लहरपुर में बकरीद पर्व से पहले सोमवार को मोहल्ला ठठेरी टोला स्थित पशु बाजार में बकरों की खरीद-बिक्री के लिए भारी भीड़ जुटी खरीदारों ने अपनी क्षमता के अनुसार बकरों की खरीद की बाजार में बकरों की कीमत 5 हजार से लेकर 40 हजार रुपए तक रही लखीमपुर और खीरी से भी लोग बकरे खरीदने पहुंचे। लखीमपुर नौरंगाबाद के आदिल ने मोहल्ला ठठेरी टोला निवासी कामरान से 95 हजार रुपए में तीन बकरे खरीदे स्थानीय निवासी रियाजुद्दीन, सगीर अहमद, सरफराज और मुशीर अहमद ने बताया कि इस बार बकरों की कीमत अधिक है शेखवापुर के मोहम्मद हफीज ने 36 हजार रुपए में एक बकरा खरीदा हरगांव से आए। ओमप्रकाश अपना बकरा उचित कीमत न मिलने के कारण वापस ले गए बाजार में बकरा बेचने वाले दुकानदारों और खरीदारों की भीड़ के कारण तहसील जाने वाले मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा!!

सूर्यांश ने बढ़ाया जिले का गौरव

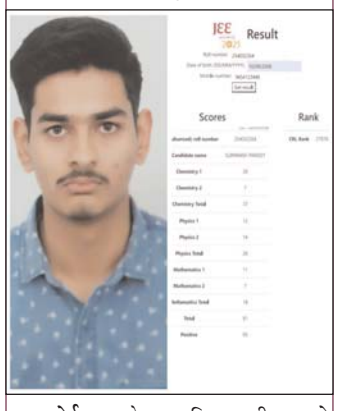

हरदोई। नगर के एक प्रतिभा शाली युवक ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा क्वालीफाई कर जिले का नाम रोशन किया है शहर के आवास विकास कॉलोनी निवासी आशीष पांडेय और मनीषा पांडेय के सुपुत्र सूर्यांश पांडेय ने जेईई एडवांस परीक्षा पास कर जिले का गौरव बढ़ाया है सूर्यांश की इंटर तक की पढ़ाई सेंट जेवियर स्कूल में हुई पिता आशीष पांडे की नगर पालिका परिषद प्रांगण स्थित शक्ति प्रिंटर्स की दुकान है। सूर्यांश शुरू से ही प्रखर बुद्धिमान छात्र रहा है कक्षा 1 से लेकर इंटर तक का सफर सेंट जेम्स स्कूल में ही पूरा किया इसके बाद जेईई मेंस क्वालीफाई किया इस बार जेईई एडवांस्ड क्वालीफाई कर जिले का गौरव बढ़ाया है।

सरकार उपेक्षा से,भड़का राशन वितरकों का गुस्सा

स्वतंत्र प्रभात

लखनऊ, उत्तर प्रदेश के कोटेदारों ने कई वर्षों से पूरे राज्य में जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों में कोटेदारों ने धरना-प्रदर्शन करते हुए खाद्य एवं रसद विभाग के खिलाफ नाराज़गी जताई। प्रदेश के हजारों कोटेदारों का आरोप है कि सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है और काम के बदले मिलने वाले मेहनताने के साथ-साथ व्यवस्थाओं में भी भारी अनियमितता बरती जा रही है।

क्या है कोटेदारों की प्रमुख मांगें?

कमीशन दर में वृद्धि की मांग- कोटेदारों का कहना है कि वर्तमान में उन्हें प्रति यूनिट पर मिलने वाला कमीशन अत्यंत कम है, जबकि पेट्रोल-डीज़ल, ट्रांसपोर्ट, मजदूरी और बिजली के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। उनका दावा है कि कई बार तो डीलर को अपनी जेब से पैसा लगाकर राशन वितरित करना पड़ता है।

पोर्टल की तकनीकी समस्याएं-

'अनाज वितरण पोर्टल' और 'ई-पॉस मशीन' अक्सर खराब रहती हैं या नेटवर्क की समस्या रहती है, जिससे राशन वितरण में बाधा आती है और उपभोक्ता नाराज़ होते हैं। कोटेदारों का आरोप है कि खराबी के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाता है।

फर्जी शिकायतों पर कार्रवाई- कई कोटेदारों ने बताया कि उन्हें बिना जांच के निलंबित कर दिया जाता है। "एक भी उपभोक्ता अगर झूठी शिकायत कर दे, तो विभाग बिना सुनवाई के कार्रवाई कर देता है। इससे हमारा मानसिक और आर्थिक शोषण होता है,"–एक कोटेदार ने बताया।

मानदेय की नियमितता- उनका यह भी कहना है कि कई महीनों से उन्हें कमीशन और अन्य खर्चों का भुगतान नहीं किया गया है। "सरकार कहती है हम 'अन्न योद्धा' हैं, लेकिन व्यवहार में हमें मजदूर से भी बदतर स्थिति में रखा गया है।"

सरकार का क्या है रुख?

खाद्य एवं रसद विभाग के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि सरकार को कोटेदारों की समस्याओं की जानकारी है और इस पर विचार किया जा रहा है। "हम जल्द ही एक समिति गठित कर उनकी समस्याओं का समाधान निकालेंगे।" हालांकि, अब तक कोई आधिकारिक बयान या ठोस आश्वासन सरकार की ओर से नहीं आया है।

प्रदर्शन का स्वरूप राज्य के करीब 75 जिलों में कोटेदारों ने राशन वितरण बंद कर 'काम बंद आंदोलन' शुरू कर दिया है। राजधानी लखनऊ में इकठ्ठा हुए हजारों कोटेदारों ने विधानसभा के बाहर मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

"हम इंसाफ चाहते हैं, दया नहीं!"

"जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, आंदोलन जारी रहेगा!" जन वितरण प्रणाली पर असर इस आंदोलन के कारण राज्य के लाखों लाभार्थियों को राशन मिलने में देरी हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर गरीब परिवारों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। निष्कर्ष उत्तर प्रदेश में कोटेदारों का यह आंदोलन सिर्फ आर्थिक मांगों का सवाल नहीं, बल्कि एक व्यापक प्रशासनिक और तकनीकी सुधार की पुकार है। अगर सरकार ने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए, तो यह संकट राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गहरा झटका दे सकता है।

क्षेत्रीय विधायक ने ग्राम पंचायत में आयोजित कैंप का किया शुभारंभ

स्वतंत्र प्रभात

बीकेटी। स्थानीय विकासखंड के ग्राम पंचायत अकड़रिया कला में शासकीय कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से एक दिवसीय कैंप का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक योगेश शुक्ला द्वारा किया गया।इस अवसर पर विधायक श्री शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सम्मान विश्व स्तर पर बढ़ा है।उत्तर प्रदेश भी विकास और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हरसंभव प्रयास कर प्रदेश के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रही है।

सहायक विकास अधिकारी विवेक शुक्ला ने बताया शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रचार प्रसार जन सामान्य में उपलब्ध कराते हुए इच्छुक पात्र लाभार्थियों को विभिन्न शासकीय कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से इस कैंप को संचालित किया जा रहा है। इस कैंप का आयोजन अकड़रिया कला ,अचरामऊ,अस्ती ग्राम से शुरू हुआ है। जो कि बारी बारी से सभी ग्राम पंचायत में आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर ग्राम प्रधान ,ग्राम सचिव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

करियर डेंटल कॉलेज में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित- सचिन बाजपेई, लखनऊ

स्वतंत्र प्रभात

लखनऊ- करियर डेंटल कॉलेज के पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री विभाग द्वारा शुक्रवार को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर एक जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन को तंबाकू सेवन के गंभीर दुष्परिणामों से अवगत कराना और तंबाकू-मुक्त समाज की ओर प्रेरित करना था।

कार्यक्रम की शुरुआत मरीजों को तंबाकू से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसानों की जानकारी देकर की गई। इसके बाद एक प्रभावशाली नाटक मंचित किया गया, जिसमें दर्शाया गया कि तंबाकू- चाहे वह सिगरेट, बीड़ी, गुटखा या खैनी के रूप में हो- शरीर के लिए एक धीमा ज़हर है। नाटक के माध्यम से यह संदेश भी दिया गया कि तंबाकू सेवन न केवल कैंसर, हृदय व फेफड़ों की बीमारियों और दांतों की समस्याओं को जन्म देता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक-सामाजिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है।

विशेषज्ञों ने बताया कि तंबाकू का दुष्प्रभाव केवल इसके सेवनकर्ता तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसके आस-पास रहने वाले लोग भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं रहते। अतः तंबाकू को मात्र आदत नहीं, बल्कि एक जानलेवा लत के रूप में समझा जाना चाहिए।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने तंबाकू से दूर रहने की शपथ ली। साथ ही, तंबाकू छोड़ने के उपायों जैसे निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, टोबैको सेसेशन काउंसलिंग और सपोर्ट ग्रुप्स की जानकारी भी साझा की गई।

कार्यक्रम का समापन एक जागरूकता रैली के साथ हुआ, जिसमें कॉलेज की प्राचार्या डॉ. बालसुंदरी श्रीधर, विभागाध्यक्ष डॉ. शीतांशु मल्होत्रा सहित अन्य चिकित्सकों, स्टाफ और विद्यार्थियों ने भाग लिया। रैली के माध्यम से "तंबाकू मुक्त समाज" का संदेश शहरवासियों तक पहुँचाया गया। करियर डेंटल कॉलेज का यह प्रयास न केवल स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाला है, बल्कि यह समाज को नशामुक्ति की दिशा में प्रेरित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल भी सिद्ध हुआ।

तंबाकू और धूम्रपान से नुकसान ही नुकसान, छोड़ने से फायदे ही फायदे- केयरिंग सोल्स फाउंडेशन

स्वतंत्र प्रभात

लखनऊ। राजधानी लखनऊ मवि श्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर केयरिंग सोल्स फाउंडेशन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मनीष मिश्रा ने कहा कि तंबाकू और निकोटीन उत्पादों से होने वाला नुकसान अब किसी से छुपा नहीं है, इसके बावजूद तंबाकू उद्योग अपनी चालाकियों और आकर्षक रणनीतियों से युवाओं को लुभाने में जुटा हुआ है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम- "अपील का पर्दाफाश- तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर उद्योगों की रणनीति को उजागर करना" - इस ओर इशारा करती है कि कैसे उद्योग स्वाद, महक और ग्लैमर का तड़का लगाकर इन हानिकारक उत्पादों को युवा पीढ़ी के बीच लोकप्रिय बना रहे हैं। मनीष मिश्रा ने कहा कि तंबाकू सेवन भारत में हर साल लगभग 12 लाख मौतों का कारण बनता है और इसके कारण 25 से अधिक बीमारियाँ व 40 से अधिक प्रकार के कैंसर होते हैं। खासकर युवाओं और गर्भवती महिलाओं के लिए यह और भी खतरनाक है। उन्होंने बताया कि कोटपा अधिनियम 2003 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को तंबाकू बेचना और शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के भीतर बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। बावजूद इसके, बाजार में नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे 2016-17 के मुताबिक भारत में लगभग 27 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, जिनमें बड़ी संख्या किशोरों की है। स्मोकिंग न केवल सेवन करने वाले के लिए घातक है, बल्कि उसके आसपास रहने वालों को भी परोक्ष रूप से प्रभावित करती है। मिश्रा ने बताया कि तंबाकू छोड़ने के फायदे तत्काल महसूस होने लगते हैं। 8 घंटे में निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर घटता है, 24 घंटे में ऑक्सीजन का स्तर सामान्य हो जाता है, 48 घंटे में स्वाद और सूंघने की क्षमता लौटने लगती है, एक माह में चेहरे की रंगत सुधरती है, 3-9 माह में सांस की दिक्कतें कम होती हैं, 5-10 वर्षों में कैंसर और हार्ट अटैक का खतरा आधा हो जाता है। केयरिंग सोल्स फाउंडेशन ने आमजन से अपील की है कि वे तंबाकू व धूम्रपान जैसी घातक लत से खुद को और अपने परिवार को दूर रखें। "आज छोड़े, कल बच" यही संदेश लेकर संगठन जनजागरूकता अभियान भी चला रहा है।

फरियादी अब एसपी से करेंगे सीधा संवाद, सीओ कार्यालयों में डिजिटल जनसुनवाई केंद्र

स्वतंत्र प्रभात

सीतापुर जनपद सीतापुर में पुलिसिंग को सुलभ, पारदर्शी और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने ऑनलाइन जनसुनवाई प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है यह डिजिटल व्यवस्था अब नागरिकों को बिना थाने या जिला मुख्यालय आए सीधे पुलिस अधीक्षक से संवाद करने का अवसर देगी विशेषकर दूरदराज के ग्रामीण, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिकायतें दर्ज करा सकेंगे इस अभिनव प्रणाली के तहत प्रत्येक क्षेत्राधिकारी (सीओ) कार्यालय को एक डिजिटल संवाद केंद्र में बदला गया है इन केंद्रों को उच्च गुणवत्ता वाले कंप्यूटर, कैमरा, माइक, हेडफोन और सुरक्षित इंटरनेट से लैस किया गया है अब सप्ताह के तय दिनों में लोग यहां पहुंचकर अपनी समस्याएं सीधे एसपी से साझा कर सकते हैं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह प्रणाली न केवल पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाएगी बल्कि सुनवाई से समाधान तक की दूरी को भी कम करेगी प्रत्येक शिकायत को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किया जाएगा और उसकी ऑनलाइन ट्रैकिंग भी संभव होगी

सभी सीओ कार्यालयों में डिजिटल जनसुनवाई केंद्र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे एसपी से संवाद, शिकायतों की रिकॉर्डिंग व डिजिटल ट्रैकिंग, तय कार्यदिवसों में शिकायत निस्तारण की व्यवस्था, महिला उत्पीड़न, साइबर क्राइम, भूमि विवाद आदि को प्राथमिकता, भ्रष्टाचार, लापरवाही या उपेक्षा पर कड़ी कार्यवाही की पारदर्शी व्यवस्था, सर्किलवार वीडियो जनसुनवाई रोस्टर:, सोमवार - सीओ नगर और सीओ सदर - सुबह 11:00 दोपहर 01, मंगलवार सीओ मिश्रिख/सीओ महोली - सुबह 11:00 दोपहर 01, बुधवार - सीओ लहरपुर/सीओ बिसवां सुबह 11:00 दोपहर 01, गुरुवार - सीओ महमूदाबाद/सीओ सिधौली - सुबह 11:00 दोपहर 01, एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि इस व्यवस्था के माध्यम से नागरिकों को लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया अनावश्यक दौड़भाग और समय की बर्बादी से मुक्ति मिलेगी यह पहल 'डिजिटल इंडिया' और 'स्मार्ट पुलिसिंग' की दिशा में सीतापुर पुलिस का स्थानीय लेकिन प्रभावशाली प्रयास है उन्होंने कहा कि हम सिर्फ समस्याएं नहीं सुनेंगे बल्कि समाधान की प्रक्रिया में भी नागरिकों को सहभागी बनाएंगे!

मूर्ति हटाने पर बवाल मामले में केस, नायब तहसीलदार समेत राजस्व टीम पर हमला, 8 नामज़द समेत 28 पर FIR

स्वतंत्र प्रभात

सीतापुर जनपद सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सरैया मसूदपुर में मंदिर की मूर्ति हटाए जाने को लेकर शनिवार को हुए भारी बवाल के बाद रविवार देर रात पुलिस ने 8 नामजद समेत 15 से 20 अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है आरोप है कि ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार राकेश कुमार, ग्राम प्रधान राधेलाल और राजस्व टीम पर लाठी डंडों से हमला कर खदेड़ दिया था ग्रामीणों का आरोप था कि राजस्व विभाग की टीम ने फावड़े और बेलचे से जबरन भगवान बालाजी की मूर्ति हटाई जिससे ग्रामीणों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। मालूम हो कि ग्रामीणों ने बताया कि उक्त जमीन पर नवनिर्मित मंदिर बनाकर भगवान बाला जी की मूर्ति चोरी-छुपे स्थापित की गई थी लेकिन शनिवार को प्रशासनिक टीम गांव पहुंची और मूर्ति को हटाने की कार्रवाई की गई आरोप है कि ग्राम प्रधान राधेलाल ने मंदिर की जमीन को श्मशान घाट घोषित करने की साजिश रची और उसी के इशारे पर राजस्व विभाग की टीम ने कार्रवाई की मूर्ति हटाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार राकेश कुमार को लाठी-डंडों से पीट दिया इसके साथ ही ग्राम प्रधान और राजस्व टीम पर भी हमला किया गया मौके पर अफरातफरी मच गई और प्रशासन को तत्काल पुलिस बल बुलाना पड़ा था स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल गांव में तैनात कर दिया गया था। उपनिरीक्षक छोटेलाल की तहरीर पर ग्रामीण संजय, अरविंद, अनिल, सुनील, शिवपूजन, विद्या, विकास और रोहित सहित 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर गवाहों के बयानों के आधार पर जांच पड़ताल कर कार्रवाई की जाएगी!!

अपनी ही जमीन से अवैध कब्जा नहीं हटवा पा रही नगर पालिका

● सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, नहीं हटवा पा रहा प्रशासन

स्वतंत्र प्रभात

हरदोई पिहानी कस्बा में रामलीला मैदान के निकट गाटा संख्या 663 में नगर पालिका की करोड़ों की भूमि पर अवैध कब्जा है। अवैध कब्जा रास्ते की भूमि है। भू माफिया सईक अपनी दबंगई व पैसे के दम पर उच्च अधिकारियों के मुंह को बंद करके रखा है। सईक मुख्य रूप से सर्कस पूरा का निवासी है जहां उसका पक्का मकान व हाउस टैक्सी रसीद कटती है परंतु इसने अपनी दबंगई के दम पर करोड़ों की नगरपालिका की जमीन अवैध रूप से कब्जा कर पक्का मकान बना दिया। राजस्व टीम के चिन्हांकित करने के बावजूद , नगर पालिका परिषद के दर्जनों नोटिस देने के बावजूद सरकारी जमीन पर बने अवैध रूप से मकान पर कोई कार्रवाई न होना जिम्मेदारों की भूमिका पर सवालिया निशान उठा रहा है। हालांकि अधिकारी इसके लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाने की बात कह रहे हैं। हाल में ही रामलीला के निकट रास्ते की भूमि गाटा संख्या 655 को नगर पालिका परिषद ने कब्जा हटाकर बोर्ड लगा दिया है। एक करोड़ से अधिक की सरकारी भूमि पर सईक निवासी सर्कस पूरा ने अवैध कब्जा कर रखा है। कब्जा सरकारी रास्ते भूमि पर हैं। कब्जा हटवाने में प्रशासन फेल हो चुका है। सभी प्रकरणों में जांच हो चुकी है। कार्रवाई के नाम पर कोरम ही पूरा किया गया है। रामलीला रोड के निकट गाटा संख्या 663 में रास्ते की भूमि करोड़ों की महंगी जमीन के मामले में प्रशासन चुप्पी साध बैठा है। लेकिन प्रशासन कुछ कर नहीं पा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेते हुए भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों को भू माफिया में चिह्नित किया जाए। इसके बाद प्रशासन ने अभियान चलाया। सरकारी जमीन कब्जा करने वाले दबंग लोगों का न तो भू माफिया में चिह्नीकरण ही किया गया और न ही उनसे जमीन ही खाली कराई गई। जिसकी वजह से शासन का अभियान फेल हो गया। जिला प्रशासन को भी पता है कि महंगी-महंगी सरकारी जमीनों पर किन-किन लोगों ने निर्माण करा लिया है फिर भी प्रशासन चुप्पी साधे है।

इस संबंध में अधिशासी अधिकारी अमित कुमार सिंह ने कहा कि सईक को कई बार नोटिस दी जा चुकी है परंतु अब सईक के साथ सख्ती से निपटा जाएगा जहां भी नगर पालिका की भूमि पर अवैध कब्जा है उसे हटाने का काम किया जा रहा है। जो लोग गलत तरीके से जमीनों पर काबिज मिलेंगे उनके खिलाफ केस भी दर्ज कराया जाएगा रामलीला मैदान के निकट गाटा संख्या 663 रास्ते के भूमि पर भू माफिया सईक का बना अवैध रूप से पक्का मकान -2 रामलीला मैदान के निकट ही गाटा संख्या 655नगर पालिका की टीम ने लाल राम निवासी मुरीदखानी से सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया।

विकास खंड कोथावां के महमूदपुर सहित दर्जनों ग्राम पंचायतों में बने अमृत सरोवर पानी विहीन

● जून की प्रचंड गर्मी में मवेंशी,पशु पक्षियों को प्यास बुझाने के लिए अमृत सरोवरों में पानी न होने से इधर-उधर भटकना पड़ रहा है।

स्वतंत्र प्रभात

कोथावां/हरदोई- क्षेत्र में जल संचयन के लिए बनाए गए अमृत सरोवर खुद प्यासे हैं। अधिकांश तालाबों में पानी ही नहीं है। इससे मवेशियों, पशु-पक्षियों की प्यास भी नहीं बुझ रही है। यहां धूल उड़ रही है। मनरेगा के तहत बन रहे इन तालाबों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। विकासखंड कोथांवा के महमूदपुर अल्होवा, सहित दर्जनों ग्राम पंचायतों में बने अमृत सरोवर तालाब धूल पाक रहे हैं जून की प्रचंड गर्मी में मवेंशी,पशु पक्षियों के प्यास बुझाने के लिए अमृत सरोवरों में पानी न होने से इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। विभागीय अफसरों को ऐसी कमियां नहीं दिखाई पड़ रही है।

अमृत सरोवरों में पानी न भरे होने को लेकर किसान यूनियन के नेता सत्येंद्र सिंह नीरज शुक्ला संतोष मिश्रा जगरूप भारती का कहना है कि ग्राम प्रधान और सचिव की बंदरबांट के चलते यह योजना कुछ गांवों में धड़ाम हो गई है। अमृत सरोवरों में पानी भरवाए जाने समय-समय पर जिम्मेदारों को अवगत कराया गया है लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है दर्जनों तालाब खाली पड़े हैं। पशु-पक्षी और ग्रामीण पानी से बेहाल हैं। बच्चे तालाब में खेलते हैं कबड्डी और क्रिकेट। मकसद तो यही था कि तालाब का सौंदर्यीकरण कराने से उसमें हर समय जल रहेगा और गांव का सौंदर्यीकरण होगा, तालाब के चारों ओर हरियाली होगी। हकीकत यह है कि कुछ तालाब को छोड़ दें तो शेष सूखे पड़े हैं। बच्चों ने उन्हें खेल का मैदान बना रखा है। कहीं क्रिकेट तो कहीं कबड्डी का खेल हो रहा है।

पौधे भी गायब । पंचायती राज विभाग ने कई तालाबों का सौंदर्यीकरण कराया था, जिनमें उनकी साफ-सफाई, खुदाई, समतलीकरण और पटरियां बनाने का कार्य शामिल रहा। लेकिन, ये अब देखरेख के अभाव में बदहाल हो रहे हैं। शासन का निर्देश था कि 15 अगस्त पर इन्हीं सरोवर तालाबों पर ध्वजारोहण किया जाएगा। उस वक्त विभागीय अधिकारियों ने तालाबों की साफ-सफाई और रंगाई-पुताई का कार्य कराया था। इसके बाद जिम्मेदार अधिकारी ने इसकी सुध लेना ही भूल गए, इसका नतीजा रहा कि सरकार की यह योजना आज ग्रामीणों के लिए बेकार साबित हो रही है। उपरोक्त विषय पर सहायक विकास अधिकारी सुधाकर वाजपेई ने बताया बंद पड़े नल व सूखे पड़े तालाबों के लिए पत्र लिखकर भेजा जा चुका है एक सप्ताह के अमृत सरोवर तालाबों की स्थिति सुधर जाएंगी।

संक्षिप्त खबरें

सिद्धार्थनगर- युवक का शव छत के पंखे से लटकता मिला

सिद्धार्थनगर जिले के सदर थाना क्षेत्र के बाल्मिकीनगर नगर में 25 वर्षीय युवक का उसी के घर में छत के पंखे से लटकता हुआ शव मिला। क्षेत्र में सनसनी फैल गई । किसी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।मृतक शशिकांत रविवार को वह अपनी बच्चों के साथ ससुराल पीपीगंज गया था। वही पत्नी व दोनों बच्चों को ससुराल छोड़ आया और शाम को वापस घर आया और खाना खाकर अपने कमरे में चला गया सुबह उसकी माँ बकरियों को घर से बाहर निकालने के लिए उठी और उसके कमरे के सामने से निकली तो देखा कि कमरे कि छत पर पंखे में शशिकान्त फांसी के फंदे से लटका हुआ है जिसे देख उसने शोर मचाया जिससे छत पर सो रहे भाई नीचे पहुंचा और फंदे को काटकर नीचे उतारा जिसके बाद पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबध में प्रभारी निरीक्षक अनुज कुमार सिंह का कहना है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है।

बच्चों को बंधक बनाकर लूट,नकाबपोश बदमाशों ने घर में रखा जेवर लेकर हो गए फरार

सिद्धार्थनगर। जिले के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र ग्राम पिपरी के टोला महजिदिया में बीती रात नकाबपोश बदमाशों ने घर में घूसकर बच्चों को उठा लिया और पटक कर जान लेने की धमकी देकर घर में रखा लगभग दो लाख के सोने चांदी के आभूषण उठा ले गये। रविवार की रात पिंपरी टोला महजिदियां निवासी पूनम पत्नी अमरजीत भोजन करने के बाद अपने बच्चों के साथ घर में सोने चली गई।रात को कुछ अज्ञात बदमाश घर मे घूस गये और सो रहे बच्चों को उठा लिया धमकी दी कि सारा जेवर लाकर दे दो वरना बच्चों को पटक दूंगा।डर के मारे घर में छिपाकर रखा टीका,अंगुठी, मंगलसूत्र,कान का झाला,कील नथुनी चांदी का पावजेब, पायल बिछिया सहित लगभग दो लाख रूपये से अधिक का जेवर उठा ले गये। नकाबपोश बदमाश जाते समय दरवाजा भी बंद कर दिया।पीड़िता ने सोमवार को थाना पर जेवरात चोरी होने की घटना की लिखित तहरीर दी। इस संबध में थाना प्रभारी बिदेश्वरी मणि त्रिपाठी का कहना है कि तहरीर मिला है। मामले की जांच की जा रही है, घटना संदिग्ध लग रहा है ,पूरे मामले की छानबीन की जा रही है।

छत के कुंडी से लटकता हुआ मिला नव विवाहित युवक का शव

सिद्धार्थनगर। जिले के जोगिया कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सुपा बक्शी में नव विवाहित युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।मृतक चंगेश उर्फ चंद्रेश (23) पुत्र जगनारायन की शादी 6 में 2025 को हुई थी। सूत्रों के अनुसार मृतक चंगेश उर्फ चंद्रेश घर की छत पर बने कमरे में था ।जब परिवार के लोगों ने उसे नहीं देखा तो छत पर जाकर देखा, जहां वह छत की कुंडी से रस्सी के सहारे फांसी के फंदे से झूल रहा था। घटना की जानकारी किसी ने पुलिस को दी, घटना की जानकारी मिलते ही प्रभारी निरीक्षक अनूप कुमार मिश्रा अपनी टीम व फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार शादी के कुछ दिनों के बाद दुल्हन मायके चली गई थी। शव को नीचे उतरते समय परिजनों का रो- रो कर बुरा हाल हो गया। इस संबध में प्रभारी निरीक्षक अनूप कुमार मिश्रा का कहना है कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों की छानबीन कर रही।

फरह थाना क्षेत्र के बॉर्डर पर लगेगा हाईटेक कैमरा

मथुरा। पुलिस ने अपराध नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। थाना प्रभारी आगरा मथुरा हाइवे रैपुरा जाट सीसीटीवी लगवाने को इंजीनियर को लोकेशन दिखाई। इस पहल को तीसरी आंख का नाम दिया गया है। आगरा मथुरा हाईवे पर अपराधी अपराध करके विभिन्न रास्तो से सुरक्षित निकल जाते है। ओर पुलिस हाथ पैर मार कर चुप रह जाती। रैपुराजाट से बलदेव, अछनेरा, ग्वालियर आदि शहर को रास्ता जाता है अब अपराधी लूट कर किधर निकल जाते है इसका पता नही लगता है अब पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसने को जगह जगह हाईटेक कैमरा लगाएगी सोमवार को थाना प्रभारी संजय पांडेय ने बॉर्डर पर कैमरा लगवाने का स्थान देखा। फरह थाना प्रभारी संजय पांडेय ने बताया कि यह कदम क्षेत्र में अपराध को नियंत्रित करने की दिशा में उठाया जा है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरों की स्थापना से न केवल अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी, बल्कि स्थानीय नागरिकों को भी सुरक्षा का अहसास होगा। बॉर्डर पर कैमरों की स्थापना से स्थानीय लोग ओर वाहन चालकों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी।स्थानीय लोगो ने इस पहल के लिए पुलिस प्रशासन का विशेष आभार व्यक्त किया है।

रंगा नदी के बाड़ में 15 से अधिक गांव क्षतिग्रस्त मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्वा शर्मा ने बाड़ प्रभावित इलाके आमतला का किया दौरा

● तीन दिनों से अरूणाचल प्रदेश में हो रही बारिश के वजह से ऊफान पर हे सियांग, ब्रह्मपुत्र नदी।

स्वतंत्र प्रभात

धेमाजी असम- गत गुरुवार से अरुणाच एवं असम में लगातार हो रही बारिश के कारण अरूणाचल एवं असम के छोटे बड़े हर नदी ऊफान पर हे । शनिवार शाम को उत्तर लखीमपुर जिले की रंगा नदी में स्थित निपको जल विद्युत प्रकल्प में अधिक पानी भर जाने से शनिवार सुबह करीब 4 बजे पानी निष्कासन के लिए गेट खुल दिया गया। नदी के निचले हिस्से में नाउबोइचा चुनावी क्षेत्र के 15 से अधिक गांव में नदी के तट तोड़कर अचानक पानी घुस जाने से लोगों में सुबह अफरातफरी मच गई ,पानी इतने जल्दी बढ़ने लगी कि लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाने की चक्कर में पशुधन, कीमती सामानों को भी नहीं निकल पाया । देखते देखते पानी बड़ी होने लगी लोगों की घर बहा ले गई,पहुमौरा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के उपर से बहने लगी। अरूणाचल प्रदेश के जीरो किमिन जाने वाले रोड के उपर से पानी बहने लगी।

दो दिन बाद आज असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्वा शर्मा में बाड़ प्रभावित इलाके की दौरा किया एवं बाड़ में क्षतिग्रस्त लोगों मिलकर की समस्या का जायजा लिया एवं कैसे इस पानी निकालने की व्यवस्था किया जाए इसपर लोगों से सलाह ली। जितना जल्दी हो सके जल निष्कासन पर काम करने इव नदी तट को पुनः निर्माण के लिए उन्होंने साथ में दौरा किया मंत्री पीयूष हजारिका को निर्देश दिया। आज मुख्यमंत्री को लखीमपु एवं नाउबोइचा के विधायक जिला प्रशासन के पदाधिकारियों ने संघ दिया।

जीवन कौशल व पर्यावरणीय गतिविधियों की सीख हासिल कर रहे समर कैंप में बच्चे

स्वतंत्र प्रभात

सिद्धार्थनगर। विकास क्षेत्र शोहरतगढ़ के कम्पोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय लेदवा में सोमवार को समर कैंप के 12 वें दिन बच्चों ने कल्पनाशील कहानी, भाषा वृक्ष बनाने का तरीका सीखा। बच्चों ने कल्पना शील कहानी और भाषा वृक्ष निर्माण कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समर कैम्प में नोडल शिक्षक मुस्तन शेरुल्लाह के नेतृत्व में बच्चों ने कल्पनाशील कहानी, भाषा वृक्ष बनाने का तरीका सीखा। समर कैंप में शिक्षक मोहन भारती ने कहा कि कल्पनाशील कहानियाँ वे कहानियाँ हैं जो पूरी तरह से कल्पना पर आधारित होती हैं। इनमें काल्पनिक पात्र, स्थान, और घटनाएं होती हैं, जो वास्तविकता से अलग होती हैं. ये कहानियाँ हमें एक अलग दुनिया में ले जाती हैं, जहां कुछ भी संभव है। कल्पनाशील कहानियाँ रचनात्मकता को बढ़ावा देती हैं और लेखकों को अपनी रचनात्मकता को उजागर करने का अवसर प्रदान करती हैं। समर कैंप के प्रारंभ में शिक्षक राकेश कुमार द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र-छात्राओं को योग व प्राणायाम का प्रशिक्षण दिया गया। समर कैम्प के बच्चों को योग के प्रति रुचि बढ़ रही है और वे नित्य योगाभ्यास भी करते हैं। चित्रकला, पोस्टर , क्राफ्ट, रंगोली, इनडोर गेम के अलावा विद्यालय में चल रहे समर कैम्प के जरिये जीवन कौशल, पर्यावरणीय व विज्ञान की विभिन्न गतिविधियों की भी जानकारी दी जा रही है। इस दौरान प्रधानाचार्य अमरेश कुमार, मुस्तन शेरुल्लाह, राकेश कुमार राज, मोहन भारती, राकेश जायसवाल, रेनू मद्धेशिया आदि लोग मौजूद रहे।

ग्राम पंचायत जटौरा के भ्रष्टाचार में बड़े जिम्मेदारों को बचाने की जुगत में उच्चाधिकारी

● मनरेगा में पेमेंट कराने में होता है मोटा कमीशनखोरी का खेल

उच्च अधिकारियों के बड़े कमीशन खोरी के चलते कागजों पर हो रहा है योजनाओं का क्रियान्वन

स्वतंत्र प्रभात

मथुरा- जनपद के ब्लॉक बल्देव में बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है जो बड़े अफसर अपनी कमीशन के खेल को चलकर छोटे कर्मचारियों पर गाज गिराने की जुगत में हैं। गौरतलब है कि विकासखंड बल्देव की ग्राम पंचायत जटौरा में बिना मजदूरों के कार्य कराए बिना ही 18 लख रुपए का काम दिखा दिया और पेमेंट भी निकाल लिया गया इस फर्जीवाड़ी की शिकायत जिला अधिकारी से की गई तो आदेश के अनुसार बीडियो बल्देव नेहा रावत ने गांव में जाकर एडीओ और एडीए के साथ जांच की तो मनरेगा के कार्यों में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया मनरेगा के तहत कार्य जैसे नाला खुदाई समतलीकरण ,मेड बंदी , चकमार्ग निर्माण आदि कराए जाते हैं भुगतान भी मजदूरों के खाते में जाता है रिपोर्ट के अनुसार किसानों के खेतों की मेड़बंदी चकमार्ग निर्माण समतलीकरण जैसे कार्यों के नाम पर प्रधान सचिव और रोजगार सेवक ने पूरे फर्जीवाड़ी को अंजाम दिया है

फर्जीवाड़ी के हुए कार्य

- संतोष कुमार के खेत की मेड़बंदी 36970
- रामकिशन के खेत की मेड़बंदी 4000053
- गुड्डु के खेत की मेड़बंदी 39816
- बबलू के खेत की मेड़बंदी 49770
- राकेश के खेत की मेड़बंदी 4000053
- ओमी के खेत से राजेंद्र के खेत तक की मेड़बंदी 165080
- दिनेश के खेत से पातीराम के खेत तक की मेड़बंदी 146102
- कैलाश चंद के खेत से सुरेश चंद के खेत तक मेड़बंदी 146064
- दिनेश के खेत से महेंद्र के खेत तक चकमार्ग का निर्माण 260700

का फर्जीवाड़ा साबित हुआ जांच में पता चला यह समतलीकरण श्रमिकों ने नहीं किया है बल्कि जेसीबी से कराया गया है मनरेगा में जेसीबी से कार्य करना प्रतिबंधित है खेल के मैदान के निर्माण में प्रयोग की गई सामग्री के नाम पर भी 7 लाख 65 हजार ?36 का भुगतान किया किया गया है जबकि जांच में यह काम अधूरा मिला।

जांच में सबसे बड़ी बात यह थी कि गांव जटौरा निवासी भगवान सिंह का कोई खेत नहीं है यह मामला भगवान सिंह तक पहुंचा तो उन्होंने भी ग्रामीणों के साथ मिलकर जांच करने की मांग की जांच में 18 लाख 19 हजार 783 के गबन का मामला सामने आया।

इस गबन की जांच में गठित हुत उच्च समिति

इस पूरे मामले में ग्राम प्रधान ने जांच पर उंगली उठाई है बिंदुवार जांच करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र सोंपा है मनीष कुमार मीणा सीडीओ ने इस मामले में चार सदस्य जांच टीम गठित की है बीडीओ नेहा रावत, मनरेगा लोकपाल डॉ अग्रसेन पांडे और लघु सिंचाई के अभर अभियंता को इस कमेटी में शामिल किया गया है। जांच टीम के मामले में जानने के लिए मनीष कुमार मीणा सीडीयो मथुरा से फोन किया गया तो फोन नहीं उठा फिर नेहा रावत बीडीयो बलदेव के द्वारा भी फोन नहीं उठाया गया।

छत की कुंडी से लटकता मिला विवाहिता का शव, पति सहित 6 लोगों पर केस दर्ज

स्वतंत्र प्रभात

सिद्धार्थनगर। जिले के मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के जबजई गांव निवासी एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। लगभग तीन पहले ही उसका विवाह हुआ था। मामले की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका का लगभग तीन वर्ष पहले ही उसका विवाह हुआ था । महिला 21 वर्षीय काजल दूबे रविवार रात में घर में चल रहे भागवत कथा को सुनकर अपने कमरे में चली गई। और दरवाजा बंद कर ली। सोमवार की सुबह जब कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो उसकी नंद गुड़िया ने दरवाजे को जोर-जोर से पीटने लगी और दरवाजा खुल गया वह अंदर देखी की उसकी भाभी काजल छत से लगे कुंडी में अपनी साड़ी से गले में फंदा बांधकर लटक गई है जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका की शादी 3 वर्ष पूर्व अनिल दुबे के साथ हुआ था। घटना की जानकारी मृतका के मायके वालों को दी गई तो मायके वाले भी मौके पर पहुंच गये। थानाध्यक्ष नारायन लाल श्रीवास्तव ने बताया कि मृतक के बाबा जनार्दन पांडेय गांव पचमोहिनी थाना गोल्हौरा निवासी तहरीर दिया है कि मेरी नतनी की शादी मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के जबजई निवासी अनिल दुबे के साथ सन 2022 में हुई थी। जब मेरी नातिन काजल विदा होकर ससुराल आई तो कुछ दिन ठीक रहा बाद में उसके पति, सास, ससुर, जेठ, जेठानी, नंद सब लोग मिलकर दहेज की मांग करने लगे कहे कि तुम अपने बाबा से बुलेट मोटरसाइकिल मागो। मेरी नातिन ने कहा जितना क्षमता था उतना दिए हैं और नहीं दे पाएंगे बार-बार दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते रहे। हम और हमारा नाती अनमोल आकर समझा बुझा कर चले जाते थे आज से एक माह पूर्व मेरी नातिन काजल को उपरोक्त लोग मार मार के घर से निकाल दिए थे सुनकर मेरा नाती काजल को आकर अपने साथ ले आया एक हफ्ते बाद परमात्मा दुबे मेरे घर आए की भागवत कथा चल रही है भेज दो मेरा नाती अनमोल अपनी बहन को मोटरसाइकिल से ससुराल पहुंचाया गया लेकिन दहेज के लोभी उसे जीने नहीं दिए उसे मारपीट कर उपरोक्त लोग उसकी हत्या करके गले में उसकी साड़ी लपेटकर छत की कुंडी में लटका दिए।

इस संबध में थानाध्यक्ष नारायन लाल श्रीवास्तव का कहना है कि तहरीर के आधार पर पति सहित 6 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

कॉरिडोरः गोस्वामियों के बाद अधिकारियों ने सुनी व्यापारियों के 'मन की बात'

● बिहारी जी कॉरिडोर समय की जरूरत, वृंदावन विकास पर खर्च होंगे 2500 करोड़

स्वतंत्र प्रभात

वृंदावन के पर्यटक सुविधा केंद्र पर आयोजित बैठक में कमिश्नर आगरा शैलेन्द्र कुमार सिंह, डीआईजी शैलेश पांडे, डीएम चंद्र प्रकाश सिंह, एसएसपी श्लोक कुमार आदि अधिकारी व्यापारियों से वार्ता करते हुए।

मथुरा। ठा. बांकेबिहारी कॉरिडोर पर गोस्वामियों से लगातार तीन दौर की वार्ता करने के बाद सोमवार को कमिश्नर और डीआईजी के नेतृत्व में अधिकारियों ने वृंदावन वासियों के मन की बात सुनी। इस मुद्दे पर आमराय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कॉरिडोर की आवश्यकता के साथ उससे होने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। गोस्वामी जनों के साथ अधिकारियों की अभी तक की वार्ता बेनतीजा रही है। बैठक में मंडलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि वृंदावन में बिहारी जी के भक्तजनों को दर्शन दौरान होने वाली दुश्वरियों से निजात दिलाने के लिए काशी के पैटर्न पर कॉरिडोर बनाया जाना है। इसके लिए न्यायालय से हरी झंडी मिल गई है। इस व्यवस्था को देखने के लिए राज्य सरकार ने बिहारी जी मंदिर न्यास की भी घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया कि शासन स्तर पर जो स्थितियां पहुंच रही हैं उन्हीं के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। वृंदावन में 2500 करोड़ की विकास परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। सोमवार को व्यापारियों के साथ टीएफसी में बैठक के दौरान अवगत कराया कि कॉरिडोर से किसी का अहित नहीं होने वाला है। श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ जाएगी। व्यापार में इजाफा होगा और अधिक लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा। बनारस इसका उदाहरण है। वृंदावन के पर्यटक सुविधा केंद्र पर आयोजित बैठक में कमिश्नर आगरा शैलेन्द्र कुमार सिंह, डीआईजी शैलेश पांडे, डीएम चंद्र प्रकाश सिंह, एसएसपी श्लोक कुमार, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्याम बहादुर सिंह, नगर आयुक्त जग प्रवेश, अपर जिलाधिकारी प्रशासन डा अमरेश कुमार, एसडीएम सदर अभिनव जैन सहित स्थानीय भाजपा नेता, पार्षद, बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे।

दुकान भी मिलेंगे, मुआवजा भी: डीएम

जिलाधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि कॉरिडोर से प्रभावित व्यापारियों को दुकान भी दी जाएंगी। निर्धारित मुआवजा दिया जाना ही है। मंदिर न्यास बनने से गोस्वामी जनों के अधिकारों में कोई कटौती नहीं होगी। सेवा पूजा पूर्ववत रहेगी। उनकी सुरक्षा के पूर्ण इंतजाम रहेंगे। कॉरिडोर और न्यास के बनने से वृंदावन के विकास के साथ बिहारी जी के भक्तों के लिए सहूलियत बढ़ जाएंगी।

'गैंग पहले जहर देता है फिर मरे पशु को उठा ले जाता है!'

● गांव जुनसुटी के ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय में दिया ज्ञापन

स्वतंत्र प्रभात

जिलाधिकारी कार्यालय पर जुनसुटी गांव के ग्रामीण ज्ञापन देने पहुंचे।

मथुरा। ग्राम सुनसुटी के ग्रामीण आज पशुओं को जहर देकर मारने के प्रकरण की जांच कराने व दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे। जहां उन्होंने डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन दिया। सुनसुटी के ग्रामीण राजेंद्र शर्मा ने बताया कि उनके ग्राम में पशु उठाने वाले गैंग ने प्रह्लाद सिंह की भैंस को जहर देकर मार दिया। यह घटना सीसी टीवी में कैद हो गई। सूचना पर पशु गैंग ने उक्त भैंस को गाड़ी में डालकर ले गया। जब उनको इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने गाड़ी वाले को फोन करके कहा कि भैंस का पोस्टमार्टम करायेंगे। लेकिन उक्त गाड़ी का चालक व उठाने वाले व्यक्ति गाड़ी को भगाकर ले गए। इसकी सूचना उन्होंने रिफाइनरी पुलिस को दी। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध नहीं की। ज्ञापन में मांग कि उक्त प्रकरण की जांच कराकर एफआईआर दर्ज की जाए, गिरोह के सदस्यों का पता लगाकर कार्रवाई की जाए, सीसी टीवी के माध्यम से आरोपियों की पहचान की जाए, आस पास के गांवों में पशुओं की हुई मृत्यु की जांच हो। ज्ञापन लेने के बाद डिप्टी कलेक्टर ने सीओ रिफाइनरी को कार्रवाई करने को लिखा है। ज्ञापन देने वालों में सुखपाल, राजेन्द्र सिंह, खजान सिंह, करन सिंह, विजय शुक्ला, प्रहलाद सिंह आदि शामिल थे।

जिलाधिकारी ने किया ग्राम आलमपुर में विकास कार्यों का निरीक्षण

स्वतंत्र प्रभात

बांदा। सोमवार को जिलाधिकारी बांदा, श्रीमती जे.रीभा ने विकासखंड बबेरू के ग्राम आलमपुर मैं तालाब के जीवन आधार कार्य एवं अन्य विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ग्राम में स्थित तालाब की खुदाई कार्य की प्रगति का जायज़ा लिया। उन्होंने खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि तालाब की खुदाई कार्य को गति प्रदान की जाए ताकि बरसात से पूर्व सभी आवश्यक कार्य समय से पूर्ण कर लिए जाएं। साथ ही उन्होंने तालाब के जीवनदायिनी आधारभूत ढांचे को मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराए जाने के निर्देश भी दिए। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने मुर्वल गांव में स्थापित टीएचआरपी प्लांट का निरीक्षण किया, जहां पर गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को दिए जाने वाले पोषाहार तैयार किया जाना पाया गया उन्होंने डीसी एनआरएलएम एवं खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिए की गुणवत्ता के साथ पोषाहार को तैयार कर आंगनबाड़ी केदो में वितरित किया जाए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्लांट में तैयार किए जा रहे प्यूषित हर एवं मां उत्पादों की गुणवत्ता की जांच की। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित किए जाने वाले कोषाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले पोषाहार में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का तत्काल पालन सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।

शहतूत वृक्षारोपण के साथ सहफसली खेती से किसानों की आय में हुई बढ़ोत्तरी

स्वतंत्र प्रभात

बांदा। प्रदेश में अधिकतर रेशम उत्पादक किसान सीमांत और लघु कृषक होते हैं। खाद्यान्न की आवश्यकता के दृष्टिगत किसानों ने खेतीबाड़ी की पुरानी परम्पराओं को अभी तक अपनाया हुआ है। रेशम उत्पादन की पद्यतियों को भी देखा जाय तो यही बात सामने आती है की अधिकतर किसान पुराने तरीकों को छोड़ने के लिए राजी नहीं होते है। इस लिए जरूरी है उनकी भूमि के एक भूखंड से ही कृषि कार्यो में विविधता लाकर आमदनी बढ़ाई जाय। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रदेश सरकार ने शहतूत वृक्षारोपण का एक सहफसली प्रारूप केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पांपोर, केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा तकनीकी स्थानांतरण हेतु संचालित किया गया है।

किसान अपनी कृषि युक्त भूमि पर इस प्रकार से शहतूत वृक्षारोपण करते हैं कि परंपरागत कृ षण कार्य भी चलता रहे और रेशम कीट पालन हेतु उसी खेत से उच्च गुणवत्ता युक्त शहतूत की पत्तियों भी प्राप्त होती रहे। केवल पहले वर्ष में नियमित पैदावार थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है किन्तु दूसरे वर्ष से इसी खेत से अतिरिक्त आय आनी शुरु हो जाएगी।यदि कोई किसान अपने खेत में 300 शहतूत के पेड़ नयी पद्धति से लगा ले और केवल दो फसलों में पत्ती बेचने (4) प्रति किलो की दर से) का काम करे तो भी वह दूसरे वर्ष में लगभग 5 हजार रूपये एवं अगले 4-5 वर्षो से इसी खेत से वह लगभग 20 हजार रूपये वार्षिक की अतिरिक्त आय केवल पत्ती बेच कर प्राप्त कर सकता है।किसान इसी शहतूत उद्यान से साल में दो फसल भी बाइवोल्टाईन रेशम कीटपालन कार्य करता है तो उचित उत्पादन के साथ वह दूसरे साल से 10 हजार रूपये का कोया उत्पादन कर सकता है और चौथी पाँचवी साल में वह 30-35 हजार मूल्य का रेशम कोया, 300 शहतूत पेड़ो की उचित रखरखाव और सफल कीटपालन से उत्पादित कर सकता है। अगर कोई किसान अपने खेत में गेहूं और मक्के की खेती कर रहा है और इसी खेत में शहतूत के पेड़ भी लगा देते हैं तो अगले 4-5 वर्षो में इसी खेत से किसान विशाल रेशम कीटपालन के साथ अपनी आय दुगुनी कर सकते है।

उचित लाभ प्राप्ति हेतु कम से कम 100 पेड़ भी स्थापित किए जा सकते है, पर 300 पेड़ का उद्यान स्थापित हो तो आर्थिक लाभ हेतु उत्तम रहता है। जितने अधिक पेड़ होंगे उसी अनुपात में पत्ती एवं तदनुसार रेशम कोया का उत्पादन अधिक होगा।यदि किसी किसान के पास जमीन कम है पर वह अधिक पेड़ लगाना चाहता है तथा रेशम कीटपालन से अधिक आय प्राप्त करना चाहता है, तो वह मेड के बाद खेत के बीच में सीधी कतार में पेड़ लगा सकता है, खेत की चौड़ाई के अनुसार कतार की संख्या निर्धारित होगी, क्योंकि दो कतारों के बीच में कम से कम 18 फीट की दूरी होनी चाहिए। इस प्रकार से एक खेत में परम्परागत खेती को प्रभावित किए बगैर किसान अपने लिए अतिरिक्त आय का एक सशक्त माध्यम कम से कम अगले 20-25 साल तक आसानी से कर सकता है। इस पद्धति से एक एकड़ जमीन में 300 शहतूत पेड़ लग सकते है। भूमि की उपलब्धता के आधार पर 100 पेड़ से 300 पेड़ तक का शहतूत उद्यान आसानी से स्थापित किया जा सकता है। प्रदेश के हजारो किसान सहफसली खेती कर खाद्यान्न के साथ-साथ रेशम के कोया उत्पादन कर अपनी अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर रहे हैं।

बालिका से दुष्कर्म करने वाले को बीस साल की सजा

● न्यायालय ने दोषी पर लगाया 11 हजार का जुर्माना

स्वतंत्र प्रभात

बांदा। शहर कोतवाली अंतर्गत मर्दननाका मोहल्ले में 12 साल पहले घर के बाहर खेल रही नौ साल की बालिका से युवक ने दुष्कर्म किया था। इस घटना में अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रदीप कुमार मिश्रा ने आरोपित को दोषी पाए जाने पर 20 साल की सजा और 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

लोक अभियोजक शिवपूजन सिंह ने बताया कि तीन जुलाई 2013 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अन्तर्गत मर्दननाका के रहने वाले अभियुक्त इस्माइल मंसूरी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया था। इस सम्बन्ध में पीड़िता के पिता ने शहर कोतवाली में तहरीर दी थी,

जिसमें उन्होंने नौ वर्षीय बेटी को शाम आठ बजे घर के बाहर खेलते समय इस्माइल मंसूरी पर मुंह दबाकर उठा ले जाने और एक सुनसान बगीचे में ले जाकर दुष्कर्म की घटना करने का आरोप लगाया था। घर लौटी बेटी ने घटना की जानकारी दी। तहरीर के आधार पर कोतवाली नगर थाना पुलिस ने धारा 376/506 भादवि व 06 पॉक्सो एक्ट में मामला पंजीकृत करते हुए कार्रवाई की। मामले की विवेचना उप निरीक्षक रामश्रय यादव ने करते हुए आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया था। लोक अभियोजक ने बताया कि पहले पुलिस ने छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन बालिका ने 164 के बयान में स्पष्ट किया था कि उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। इसके आधार पर तहरीर में बदलाव कर दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई गई। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान सुने। उनकी ओर से छह गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने इस्माइल मंसूरी को दोषी पाए जाने पर 20 साल की सजा और 11000 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है।